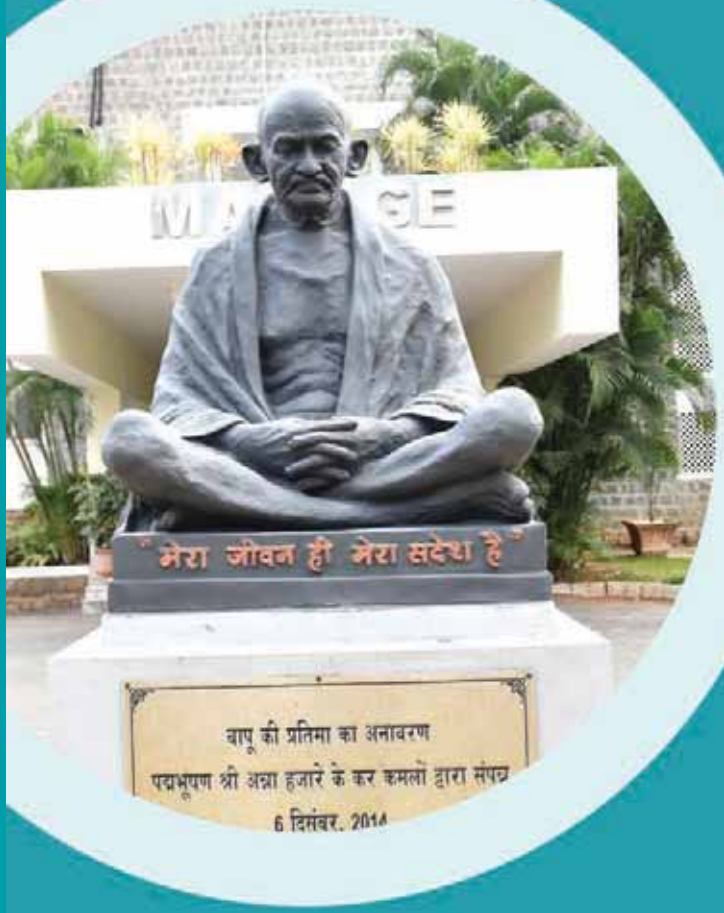

MANAGE
मैनेज

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना, भारत
www.manage.gov.in

मैनेज
वार्षिक प्रतिवेदन
2019-2020

MANAGE
मैनेज

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030 तेलंगाना, भारत.
www.manage.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	महानिदेशक का संदेश	
1	मैनेज - एक परिचय	1
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019-20	10
3	अनुसंधान और परामर्श	19
4	योजनाएँ	
	एग्री क्लिनिक्स तथा एग्री बिजिनेस केन्द्र योजना (एसी व एबीसी)	24
	एक्वा क्लिनिक्स और एक्वा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एसी व एडीपी)	32
	इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (देसी)	36
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार)	39
	ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई)	43
	फर्टिलाइजर डीलर्स के लिए एकीकृत पोषण प्रबंधन (सीसीआईएनएम) पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	44
5	शिक्षा कार्यक्रम	
	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि व्यवसाय प्रबंध) [(पीजीडीएम) (एबीएम)]	46
	स्नातकोतर कृषि भण्डारण प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)	53
	प्रामाणिक क्षेत्र सलाहकार/प्रामाणिक पशुधन सलाहकार कार्यक्रम	56
	कृषि-भंडारण प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीएडव्ल्यूएम)	59
6	सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का सहयोग	60
7	पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन	62
8	राजभाषा की प्रगति	64
9	प्रशासन एवं लेखा	65
10	परिशिष्ट	
	परिशिष्ट I – मैनेज की महापरिषद के सदस्य	69
	परिशिष्ट II - मैनेज की कार्यकारी परिषद के सदस्य	72
	परिशिष्ट III – मैनेज संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची	74

महानिदेशक का संदेश

माँग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय कृषि विस्तार प्रबंधकों का क्षमता निर्माण मैनेज का मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान मैनेज ने 4761 प्रतिभागियों के लिए 182 प्रशिक्षणों का आयोजन किया है। मैनेज ने वर्तमान प्रासंगिक विषयों जैसे किसानों की आय को दुगुना करना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, कृषि विस्तार की नयी सीमाएं, लिंग संवेदिता और जेन्डर कर्मियों की नीति अधिवक्तृता पर महत्वपूर्ण कार्यशालाएं व संगोष्ठियों का आयोजन भी किया है।

इस वर्ष के दौरान, दस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन फीड दि फ्यूचर इंडिया त्रिकोणीय प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य राष्ट्र स्तरीय संस्थानों के तत्वधान में विशेष तकनीकी विषयों पर आयोजित किए गए हैं। सतत कृषि विकास हेतु विस्तार दृष्टिकोण पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सटेन्शन के सहयोग द्वारा मैनेज ने सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कृषि समुदाय पर प्रभाव डालने के लिए "पाथवेस ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन फर एनहैन्सिंग फुड एण्ड न्यूट्रिशनल सेक्यूरिटी एण्ड डिवलपमेंट" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

संस्थानात्मक सहयोग बढ़ाने के लिए, मैनेज ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), नई दिल्ली के साथ कृषि अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। मैनेज ने, जर्मन एग्रिकल्चरल एकाडमि, डी ई यू एल ए, नैनबर्ग के साथ तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में विशिष्ठ क्षेत्रों के लिए समझौते के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्टेम मैनेजमेंट और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की संगठनात्मक प्रक्रिया, नवीन प्रशिक्षण विधियों का प्रारंभ, सूचना और सलाह देना है।

मैनेज भारत सरकार की उन्नत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी कर रहा है जिसमें ए सी ए बी सी, पी जी डी ए ई एम, डी ए ई एस आई और एस टी आर वाई समाहित है। वर्ष 2019-20 में इन योजनाओं के माध्यम से मैनेज ने 6955 कृषि उद्यमियों को, 13306 विस्तार व्यवसायियों को, 20920 इनपुट डीलरों तथा 7500 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है। मैनेज इन्कुबेशन गतिविधियों के माध्यम से कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करता है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरूद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आर के वी वाई - रफतार) योजना का कार्यान्वयन करता है। इस वर्ष के दौरान, 18 एग्रि स्टार्टअप्स चुने गए है और उन्हें अनुदान सहायत प्रदान की गयी है।

यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैनेज के कृषि व्यापार प्रबंधन स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पी जी डी एम - ए बी एम) को एक बार फिर 100 प्रतिशत कैम्पस प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। भारत के उत्तम कॉलेजों में मैनेज को 40 वां रैंक, अध्ययन अनुभव में 12 वां स्थान और भारत में लिविंग एक्सप्रीरिएन्स में 22वां स्थान बिजिनेस टुडे 2019 द्वारा प्रदान किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान मैनेज ने ग्यारह छात्रों/रीसर्च स्कॉलरों को इन्टर्नशिप (3 महीने / 6 महीने) प्रदान किया है। वे छात्र देश के विभिन्न नामी कृषि विश्वविद्यालयों से है और उन्हें अनुभवात्मक शिक्षण व विस्तार शिक्षा के नवीन विषयों को सीखने, अनुप्रयुक्त अनुभव प्राप्त करने, व्यावसायिक गतिशीलता विकास और कृषि विस्तार हितधारकों के बीच नेटवर्क स्थापन का अवसर प्रदान किया है।

हमारी सफलता का श्रेय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, हमारी महापरिषद, कार्यकारी परिषद अकादमिक समिति से प्राप्त निरंतर समर्थन को जाता है। कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य कृषि एवं संबद्ध विभागों, समेतियों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, ई ई आई तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त समर्थन के प्रति भी हम आभार प्रकट करते है। हम भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त करते है।

श्रीमती जी. जयलक्ष्मी भा.प्र.से.
महानिदेशक

1. मैनेज- एक परिचय

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष 1987 में स्थापित किया गया है। जिसकी स्थापना तेजी से बढती हुई उन्नति तथा कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में कृषि विस्तार प्रबंधन के राष्ट्रीय केन्द्र के रुप में हैदराबाद में हुई है। उसके महत्व और गतिविधियों की व्यापकता के मद्दे नजर, उसके स्तर को 1992 में राष्ट्र स्तर की संस्थान के रूप में बढ़ाया गया और उसे राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के रूप में पुन: नामांकन किया गया।

मैनेज को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में दिनांक 11 जून, 1987 में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) के अंतर्गत सार्वजनिक सोसाइटी में पंजीकरण अधिनियम, 1350 फसली (1350 एफ का अधिनियम) के तहत पंजीकृत किया गया।

अधिदेशानुसार मैनेज को विस्तार कर्मियों के ज्ञान, कौशल तथा व्यवहार में बढोत्तरी सहित कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा सेवा सुपुर्दगी तंत्रों को विकसित करने में भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है।

मिशन

मैनेज का मिशन कृषि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारी, प्रबंधक, वैज्ञानिक और प्रशासनिकों द्वारा प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल प्राप्त करने में सहायता करना, जिससे सतत कृषि अपनाने के लिए किसानों और मछुवारों को समर्थ बनाने में सहायता उपलब्ध हो सके।

विज़न

विश्व में अग्रणी, नवोन्मेषी, प्रयोक्ता स्नेही तथा स्व-समर्थित कृषि प्रबंध संस्थानों में शामिल होना है।

अधिदेश

- कृषि विस्तार प्रबंध तथा कृषि विकास से संबंधित मुख्य राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयोजन विकसित करना।
- कृषि विस्तार प्रबंध और नीतियों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना
- संकाय संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक संयोजनों को बढाना।
- कृषि विस्तार संस्थानो की प्रभावशालिता में सुधार हेतु आधुनिक प्रबंध उपकरणों के अनुप्रयोग का विकास और बढाना।
- वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- कृषि विस्तार प्रबंध पर समस्या अभिमुख अध्ययन का आयोजन करना।
- कृषि विस्तार प्रबंध संबंधी विषयों पर सूचना का संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण तथा संचरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रुप में काम करना है।

मुख्य मूल्य

- उपभोक्ता मैत्री
- ग्राहक सकेन्द्र प्रक्रिया परामर्श
- सभी व्यावसायिक सेवाओं में किसान सकेन्द्रित दृष्टकोण
- प्रतिक्रियात्मक और प्रयोगात्मक रुप से सीखने की क्रियाविधि
- फेसिलिटेटरों के साथ संकाय विकास और नेटवर्किंग
- वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का दृढ संकल्प

संस्थान का ध्यान चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने के अलावा प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श आदि पर है।

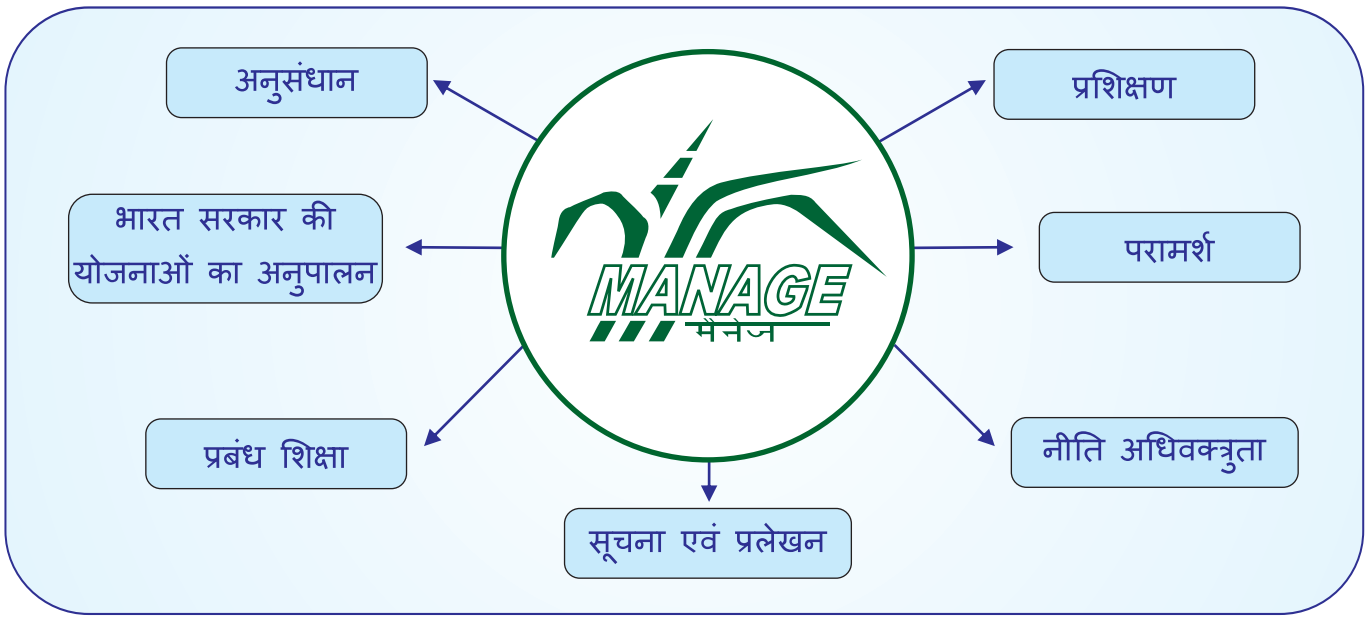

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण मैनेज के अधिदेश का आन्तरिक भाग है और यह विस्तार व्यवसायियों के लिए किसानों को कृषि विस्तार व सलाहकारी सेवा दक्षता के साथ देने हेतु अपने ज्ञान व क्षमताओं को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विस्तार कर्मियों को उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु सक्षम बनाने की आवश्यकता है। मैनेज सरकारी विस्तार कर्मी जो विभिन्न राज्यों व केंद्र प्रदेशों के कृषि, बागवानी, पशुपालन व पशुचिकित्सा विज्ञान, मत्स्यपालन, कोशकीट पालन आदि विभागों, के वी के व आई सी ए आर के वैज्ञानिकों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के कार्यकारियों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यशालाएं व पुनश्चर्या कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम कृषि विस्तार प्रबंधन के वर्तमान विषय वस्तुओं पर समझ प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते है। मैनेज प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान केन्द्रित होता है। मैनेज के प्रशिक्षण कर्यक्रमों की सफलता भागीदारी व अनुभावात्मक शिक्षण विधि, केस स्टडीज, सफल कहानियों, कार्यानुभव, शिक्षण दौरे, समूह कार्य, सॉफ्ट स्किल्स व संपर्क कौशल अंतर क्रियात्मक सत्र, विचार विमर्श, प्रजेन्टेशन और तकनीकी सूत्रों पर निर्भर है। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मैनेज किसानों, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारां सामना किए गए क्षेत्र स्तर की कठिनाईयों से निपटने की विधि में विश्वास रखता है।

इन कार्यक्रमों का आयोजन मैनेज में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। यह कार्यशाला प्रशिक्षण की जरूरतों पर ब्रेनस्टार्म करने में विस्तार शिक्षण संस्थानों (ई ई आई) के प्रतिनिधियों की भगीदारी के साथ संभावित सहयोग, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती), कृषि विभाग एवं संबंद्ध क्षेत्र और आई सी ए आर/ एस ए यू के वैज्ञानिकों के लिए एक मंच प्रदान करती है। मैनेज के कार्यक्रम भारत सरकार/केन्द्र शासित संगठन तथा निजी क्षेत्र के अनुरोध के अनुरूप भी तैयार किए जाते हैं।

अनुसंधान व परामर्श कार्य

मैनेज कृषि विस्तार प्रबंधन में समकालीन प्रासंगिक विषयों पर अनुसंधान करता है जैसे किसानों को बाजारों से जोड़ना, जलवायु परिवर्तन, खाद्य व पोषण सुरक्षा, जेंडर मद, आई सी टी अप्लिकेशन आदि। मैनेज एक्शन रिसर्च को क्षेत्र परिस्थितियों में विचार / अवधारणाओं / प्रौद्योगिकियों को पइलट परीक्षण करने के लिए लिया जाता है। अनुरोध किए जाने पर राज्य विभागों के लिए परामर्शी सेवा भी प्रदान की जाती है। विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन को केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी संगठनों के अनुरोध पर किया जाता है।

शिक्षा कार्यक्रम

मैनेज के शिक्षा कार्यक्रमों में कृषि व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी जी डी एम (ए बी एम)], कृषि विस्तार प्रबंध स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी जी डी ए ई एम), प्रमाणित फार्म सलाहकार / प्रमाणित पशुधन सलाहकार (सी एफ ए / सी एल ए) और स्नातकोत्तर कृषि भण्डारण प्रबंध डिप्लोमा (पी जी डी ए डब्ल्यू एम) समाहित है।

पी जी डी एम (ए बी एम) मैनेज का द्विवर्षीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो बिजिनेस लीडरों और टेक्नो - मैनेजरों को तैयार करता है। पी जी डी ए ई एम दूरस्थशिक्षा प्रणाली पर सेवारत विस्तार कर्मियों के लिए प्रदत्त एक वर्षीय निरंतर शिक्षा कार्यक्रम है जिसके कॉन्टेक्ट कक्षाएँ संबंधित राज्य मुख्यालयों में आयोजित की जाती है। प्रमाणित फार्म सलाहकार / प्रमाणित पशुधन सलाहकार कार्यक्रम का लक्ष्य एक विशेष फसल / पशुधन पर कृषि विस्तार कर्मियों को विशेषज्ञों के रूप में विकसित करना है। पी जी डी ए डब्ल्यू एम का लक्ष्य प्रवेश प्राप्त आवेदकों को कृषि भण्डारण के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों के साथ समृद्ध बनाना है।

सरकारी योजनाएं

मैनेज भारत सरकार की योजनाएं जैसे एग्रि क्लिनिक्स व एग्रि बिजिनेस सेन्टर्स योजना (ए सी व ए बी सी), इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (डी ए ई एस आई), ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एस टी आर वाई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं सबंद्ध क्षेत्र पुनरूद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आर के वी वाई - रफ्तार) योजना का कार्यान्वयन भी करता है।

ए सी ए बी सी योजना का कार्यान्वयन कृषि - व्यवसायियों में कृषि उद्यमिता कौशलों को बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। देसी कार्यक्रम का प्रारंभ इनपुट डीलरों को संपर्क कक्षा - सह - दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के आधार पर कृषि के तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षित करने हेतु किया गया है। एस टी आर वाई योजना का लक्ष्य कृषि आधारित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को कौशलों से युक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। आर के वी वाई रफ्तार योजना का लक्ष्य देश में कृषि उद्यमिता और कृषि व्यापर परिवेश का निर्माण का निर्माण कर कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों के इन्फास्ट्रक्चर को दृढ़ बनाना, संभाव्य एग्रिस्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना और बिजिनेस इन्कुबेशन व्यवस्था का पोषण करना है। एक्वा क्लिनिक्स और एक्वाप्रेन्यूरशिप विकास कार्यक्रम (ए सी व ए डी पी) राष्ट्रीय मतिस्यकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) के सहयोग से मैनेज द्वारा आयोजित एक और कार्यक्रम है।

मैनेज में केंद्र

मैनेज के मुख्य क्रियाकलाप निम्न केन्द्रों एवं एक कृषि व्यापार प्रबंधन स्कूल के माध्यम से चलाये जाते हैं, केन्द्र का विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. कृषि विस्तार नीति, सरकारी निजी भागीदारिता एवं कृषि विस्तार में अंतरर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता का केंद्र
2. कृषि विस्तार नवोन्मेशन, सुधार एवं कृषि उद्यमिता का केंद्र
3. कृषि संस्थानों के क्षमता निर्माण का केंद्र
4. कृषि विस्तार में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा विपण्न का केंद्र
5. कृषि संबद्ध क्षेत्रों में विस्तार का केंद्र
6. कृषि विस्तार में ज्ञान प्रबंधन आईसीटी तथा मास मीडीया का केंद्र
7. कृषि में जेन्डर, पौष्टिक सुरक्षा एवं शहरी कृषि का केंद्र
8. सतत कृषि, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मूल्यांकन एवं संवीक्षण का केंद्र
9. जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन का केंद्र और
10. कृषि व्यापार प्रबंध स्कूल

वर्ष 2019 – 20 के नवीन कार्य व कार्यक्रम

जर्मन एग्रिकल्चरल एकाडमी, डी ई यू एल ए, नैनबर्ग के साथ मैनेज का समझौते का ज्ञापन:

मैनेज और जर्मन एग्रिकल्चरल एकाडमी, डी ई यू एल ए, नैनबर्ग ने तकनीकी और व्यापारिक प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों में सहयोग हेतु सहमत हुए है। इस में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना, स्टेम मैनेजमेंट और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संगठनात्मक प्रक्रिया, नवीन प्रशिण विधियों का परिचय, सूचना और सलाह आदि सम्मिलित है।

मैनेज का आई सी ए आर के साथ समझौते का ज्ञापन

मैनेज ने कृषि भवन, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), नई दिल्ली के साथ 24 जून, 2019 को समझौते के ज्ञापन से जुड़ा है । यह एक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के उद्देश्य से किया गया है। मैनेज और आई सी ए आर अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सहमत हुए है। वर्ष 2019 – 2020 के दौरान मैनेज ने आई सी ए आर संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ 30 तकनीकी आधारित सहयोगात्मक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए जुड़ा है। 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण हुए है।

महत्वपूर्ण सहयोगात्मक कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम

मैनेज - एम एस यू एक्सटेन्शन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

कृषि विस्तार के नवीन रास्तों के लिए अपने उच्च अनुभव के आदान प्रदान के लिए, मैनेज और मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सटेनशन द्वारा संयुक्त रूप से "पाथ वेस ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन फॉर एन्हैन्सिंग फुड एण्ड न्यूट्रिशनल सेक्यूरिटी एण्ड डिवलपमेंट" पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 18-19 फरवरी, 2020 को मैनेज में आयोजित किया गया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य सततत कृषि और ग्रामीण विकास हेतु कृषक समाज में परिवर्तन लाने के लिए विस्तार और सलाहकार सेवा को दृढ़ बनाने के लिए एकीकृत कार्रवाई और सुधार करना है। राज्य विभागों, समेतियों, ई ई आई, के वी के, आई सी ए आर, अटारी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, इक्रिसाट, एन आई एन, एन आई पी एच एम से 68 प्रतिनिधियों और मैनेज के संकाय सदस्य इस कार्यशाला में भाग लिए है।

फीड द फ्यूचर भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफ टी एफ आई टी टी)

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 10 फीड द फ्यूचर भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एफ टी एफ - आई टी टी) का आयोजन किया गया है जिसमें आसिया और अफ्रीकी के 17 देशों से 257 प्रतिनिधि कार्यकारियों ने भाग लिया। इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और भारत के अन्य नामी संगठनों के सहयोग से आयोजित किए गए हैं।

"सतत कृषि विकास हेतु कृषि विस्तार दृष्टिकोण" पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहकारिता (आई टेक) प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज में आयोजित किया गया है।

मूल्यांकन क्षमता का निर्माण : सेवारत कृषि और ग्रामीण विकास व्यवसायियों के लिए एक अल्पावधि पाठ्यक्रम: मैनेज एन आई आर डी व पी आर-एम एस यू

कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाएं / योजनाएं / कार्यक्रमों के मूल्यांकन की मांग को दृष्टि में रखते हुए मैनेज और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज संस्थान ने मिचिगन स्टेट यूनिवर्सीटी यू एस ऐ के सहयोग से दो प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए है। मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधक व्यक्ति प्रो. मुरारी सुवेदी और अन्य संसाधक व्यक्तियों द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों / संकाय / वैज्ञानिकों को मूल्यांकन विशेषज्ञ / मूल्यांकन प्रशिक्षक बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया ।

सतत आजीविका व जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन (एस एल ए सी सी) पर एन आई आर डी व पी आर प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का केन्द्र (सी एन आर एम), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने "सतत आजीविका व जलवायु परिवर्तन अनुकूलन" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे जिसमें 200 सामुदायिक संसाधक (सी आर पी) और 100 राष्ट्रीय संसाध, (एन आर पी) मिशन कर्मचारी सम्मिलित थे। मैनेज इस कार्यक्रम के लिए थर्ड पार्टी मूल्यांकन करेगा और प्रमाणन प्राधिकारी होगा।

यू एन डी पी दिशा –एक्सेस लाइवलीहुड्स इंडिया लिमिटेड (ए एल सी) व्यापार उद्यमिता नेतृत्व प्रबंधन कार्यक्रम के लिए ज्ञान और मूल्यांकन भागीदार के रूप में मैनेज

उच्च समुदायों को तैयार करने तथा ग्रामीण समाजों में परिवर्तन लाने के लिए एक्सिस लाइवलीहुड्स कन्सल्टिंग इंडिया लिमिटेड ने दिशा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के समर्थन से भारत में महिलाओं के लिए

रोजगार व उद्यमिता अवसर प्रदान करने के लिए व्यापार उद्यमिता नेतृत्व प्रबंधन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। ए एल सी और यू एन डी पी - दिशा के साथ मैनेज ने इस कार्यक्रम के मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु भागीदार बना है।

इंडियन स्कूल ऑफ बिजिनेस (आई एस बी) में 100 ग्रामीण महिलाओं का ए एल सी - यू एन डी पी - मैनेज प्रमाणन

सामुदायिक संसाधक - फार्म लाइलीहुड्स (सी आर पी - एफ एल), डे-एन आर एल एम का ज्ञान आकलन और प्रमाणन ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीन लाइवलीहुड्स मिशन (डी ए वाई - एन आर एल एम) को जून, 2011से चला रहा है। एन आर एल एम मिशन सामुदायिक व्यवसायियों केा माध्यम से निरंतर समर्थन प्रदान करता है यथा सतत आजीविका के प्रोत्साहन हेतु (1) पशु सखी (2) कृषि सखी। सी आर पी यों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता के आश्वासन के लिए, मिशन सभी प्रशिक्षित सी आर पी यों को ज्ञान आंकलन और फार्म लाइवलीहुड्स ज्ञान आंकलन और प्रमाणन प्रोटोकाल की स्थापना के लिए मैनेज नोडल एजेन्सी है।

मैनेज, हैदराबाद में फरवरी 10 और 11 को आजीविका स्थानीय संसाधक व्यक्तियों के लिए संस्थागत व्यवस्था और प्रशिक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय अनुस्थापन कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विधि और सी आर पी प्रमाणन हेतु प्रश्नावली पर चर्चा करने और उसका निर्धारण करने हेतु मिशन मैनेजरों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि एन आर पी यों और एल आर पी यों ने भाग लिया।

इन्टर्नशिप कार्यक्रम

मैनेज इन्टर्नशिप कार्यक्रमों का लक्ष्य व्यावसायिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष उपयोग और कौशल विकास के साथ विस्तार शिक्षा में ज्ञान और सिद्धांत के समाकलन के लिए अनुभावात्मक अध्ययन प्रदान करना है। इन्टर्नशिप छात्रों को विस्तार शिक्षा के वर्तमान विषयों को सीखने, महत्वपूर्ण अनुप्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने तथा कृषि विस्तार के हितधारकों के बीच व्यावसायिक नेटवर्क विकास करने को सरल बनाने के अवसर प्रदान करता है। यह इन्टर्नशिप के एम एस सी और पी एच डी शोधार्थीयों के लिए खुला है। मैनेज ने जून-दिसंबर, 2019 के दौरान देश के नामी विश्वविद्यालयों के 11 छात्र/शोर्धियों को इन्टर्नशिप प्रदान किया है।

पुरस्कार

राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार - 2019

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार प्रारंभ किया है जिसके द्वारा भारत में उद्यमिता की ओर लोगों की विचारधारा को मोड़ने के लिए युवाओं में उद्यमिता प्रवृत्ति को बढ़ा सके। इसमें अन्य ग्यारह संस्थानों के साथ मैनेज भी एक कार्यान्वयन भागीदारी है। मैनेज इन पुरस्कारें को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों, रोड शो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

राजभाषा कार्यान्यन हेतु पुरस्कार

मैनेज को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद-सिकंदराबाद द्वारा 100 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों के तहत द्वितीय उत्तम कार्यान्वयन कार्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों का दौरा

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा मैनेज का दौरा

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने 27 सितंबर, 2019 को मैनेज का दौरा किया और संकाय, पी जी डी एम (ए बी एम) के छात्र और भागीदारों के साथ चर्चा की। श्री डी. अरविन्द, सांसद, निजामाबाद, तेलंगाना राज्य और श्री राजेश वर्मा, भा.प्र.से., अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण

मंत्रालय भी इस परिचर्चा में भाग लिए। एन आई पी एच एम, नारम, आई आई एम आर, आई आई ओ आर, डी पी आर और ए टी ए आर आई जैसे पड़ोसी संस्थानों के अध्यक्ष भी परिचर्चा में भाग लिए।

श्री कैलाश चौधरी, माननीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा मैनेज का दौरा

श्री कैलाश चौधरी, माननीय कृषि राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 26 जून, 2019 को मैनेज का दौरा किया गया और संकाय के साथ चर्चा की गयी। श्री संजय अग्रवाल, सचिव कृषि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने भी इस परिचर्चा में भाग लिया।

यू एस ए आई डी टीम द्वारा मैनेज का दौरा

मिस पमेला मोरिस, मि.जे. रॉबर्ट सिम्मन्स और डॉ. विजु आईपे सहित यू एस ए आई डी की एक मूल्यांकन समिति ने 10 मई, 2019 को मैनेज का दौरा किया। इसका उद्देश्य खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा में मानवीय तथा संस्थानात्मक क्षमता की कमियों की पूर्ती में फीड दि फ्यूचर भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण (एफ टी एफ - आई टी टी) के प्रभाव का मापन, अभिलेख और निर्धारण करना था। इस दल ने महानिदेशक, मैनेज और संकाय के साथ चर्चा की।

भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विचारों के आदान प्रदान पर चर्चा करने के लिए मि.मार्क. ए. वाईट, मिशन निदेशक, यू एस ए आई डी - भारत, मि. मुस्तफा एल हमजाई, निदेशक खाद्य सुरक्षा कार्यालय, यू एस ए आई डी भारत और श्री वंशीधर रेड्डी टी एस, डिवलपमेंट एसिस्टेन्स स्पेशलिस्ट (कृषि), खाद्य सुरक्षा कार्यालय, यू एस ए आई डी भारत ने 10 जून, 2019 को मैनेज का दौरा किया।

मि. कीथ ई सिम्मन्स, मिशन निदेशक, यू एस ए आई डी, भारत ने अपने दल के साथ 1 नवंबर, 2019 को मैनेज का दौरा किया और एफ टी एफ - आई टी टी कार्यक्रम और भविष्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। मिशन निदेशक और उनके दल ने महानिदेशक और मैनेज संकाय के साथ परिचर्चा की।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019-20

मैनेज, राज्यों के कृषि, बागवानी, पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवा, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन विभागों, में कार्य करने वाले वरिष्ठ और मध्य स्तर के कृषि विस्तार पेशेवरों तथा राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के लिए चुने गये विषयगत क्षेत्रों पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है। नई चुनौतियों का सामना करने और सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विस्तार कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए वर्तमान महत्व के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। मैनेज भारत सरकार, राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों, संगठनों तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के अनुरोध पर अनुकूलित प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (कस्टमाइज्ड इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम) और रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और संबद्ध विभागों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आसीएआर) के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों (एसएएमईटीआई), विस्तार शिक्षा संस्थानों (ईईआई) के संकाय सदस्यों आई सी ए आर सश्याना के वैज्ञानिक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के विकास संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी मैनेज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मैनेज एशियाई और अफ्रीकी देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को द्वि-पक्षीय और बहु-पक्षीय समझौतों के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है.

रूपरेखा और नियोजन

मैनेज ने अकादमिक समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श के पश्चात अकादिमक वर्ष 2019-20 के लिए कृषि विस्तार व्यवसायियों के लिए उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करने निम्न तीन मापों को अपनाया है।

1. सर्वेक्षण: देश के कृषि विस्तार व्यवसायियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर मैनेज ने एक प्रश्नावली के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया है। एक 1000 से अधिक अधिकारियों / वैज्ञानिकों/ अकादमिक व्यक्तियों / अभ्यास के जो राज्य विभागों, आत्मा कर्मियों, समेतियों, ई ई आई, आई सी ए आर, के वी के, अटारी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार निदेशालयों के और एन जी ओ के प्रतिनिधियों को पोस्ट द्वारा भेजा गया और ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्नावली द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने थीम्स / टॉपिक्स के महत्व पर अधिकारियों / वैज्ञानिकों से सूचना/डैटा प्राप्त किया जा सकता है। 45 थीम्स/विषयों को सूचित किया गया है और 5 पाईंट स्केल पर (बिल्कुल उपयुक्त नहीं = 1; अत्यंत महत्वपूर्ण = 5) उनके महत्व को सूचित करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त समाधान के आधार पर विषयों की अधिकारियों के लिए उनके महत्व के आधार पर विषयों की प्राथमिकता सूची तैयार की गयी है। प्रथम 20 विषयों की सूची निम्नानुसार है।

रैंक	थीम / टॉपिक
1	किसान की आय को दुगना करना
2	किसानों को बाजारों से जोड़ना
3	जल प्रबंधन
4	किसान उत्पादक संगठन
5	नव नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण
6	कृषि में जलवायु परिवर्तन
7	कृषि में आई.सी.टी.
8	कृषि उद्यमिता में महिलाएं
9	कृषि में युवा
10	जैविक कृषि
11	वर्षाधारित कृषि में विस्तार
12	बाजार चालित विस्तार
13	अभिलेखन कौशल
14	व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
15	विस्तार व्यवस्था में कार्य नीति
16	विस्तार के लिए सामाजिक कौशल
17	कृषि निर्यात प्रबंधन
18	कृषि ज्ञान प्रबंधन
19	कृषि उत्पाद के लिए मूल्य जोड़ का प्रबंधन
20	कृषि में सोशल मीडिया

उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारी के समय विचार किया गया और यह आश्वासन दिया गया है कि 2019-2020 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक विषय पर कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

2. प्रतिभागियों का फीडबैक : मैनेज अपने प्रशिक्षणों के डैटाबेस का फीडबैक सहित रखरखाव करता है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान मैनेज प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फीडबैक का विश्लेषण प्रशिक्षणों की प्रभावशालिता को जानने के लिए किया गया और फीडबैक रैंकों के आधार पर अत्यंत प्रभावी कार्यक्रमों की पहचान कर 2019-2020 अकादमिक वर्ष में जोड़ने हेतु विचार किया गया। वर्ष 2019-2020 अकादमिक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तावित करते समय प्रतिभागियों का फीडबैक और प्रत्येक प्रशिक्षण के रैंकिंग पर विचार किया गया है। फीडबैक के परिणामों का उपयोग निरंतरता से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

3. संकाय के प्रस्ताव : मैनेज केंद्रों के संकाय सदस्य, विस्तार में प्रशिक्षण व दक्षता निर्माण में प्राप्त अनुभव के अनुसार थीम आधारित ऑनकैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य विशेष के ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तावित किए है।

4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम: मैनेज ने 91 आई सी ए आर संस्थानों तथ 47 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी विस्तार व्यवसायियों के लिए तकनीकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफ कैम्पस सहयोगात्मक कार्यक्रमों के रूप में प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया है। इस पर विभिन्न नवीन कृषि तकनीकियों पर आई सी ए आर संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से कुल 124 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। महानिदेशक मैनेज की अध्यक्षता में निदेशकों के साथ गठित एक समिति द्वारा इन प्रस्तावों की समीक्षा की गयी और 29 तकनीकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पहचाना गया जो कि विस्तार व्यवसायियों के लिए संबद्ध है।

वर्ष 2019 - 2020 के लिए विस्तार अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन और योजना बनाने के लिए उपरोक्त दृष्टिकोणों का पालन किया गया है।

विधि

मैनेज के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दक्षता का आधार भागीदारी और अनुभवात्मक शिक्षण विधि, केस स्टडीज, सफल कहानियाँ, अभ्यास, फील्ड विजिट, सामूहिक कार्य, सॉफ्ट स्किल्स, संपर्क कौशल, वार्तालाप सत्र, विचार विमर्श, भागीदारों के प्रजन्टेशन, मैनेज संकाय और भारत के नामी संस्थाओं से आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी सत्र है। मैनेज अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों, अधिकारियों और अन्य हितधारक द्वारा क्षेत्र स्तर पर सामना किए जा रहे मामलों के लिए समस्या-समाधान दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। मैनेज अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पठन सामग्री और अभ्यासों के अलावा वेबिनार, वीडियो आदि का भी उपयोग करता है।

अकादमिकि समिति

मैनेज की अकादमिक सिमिति की 23वीं बैठक महानिदेशक, मैनेज की अध्यक्षता में 7 फरवरी, 2019 को संपन्न हुई और इस बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 35 स्कीम आधारित कार्यक्रम और दो अनुसंधान अध्ययन अनुमोदित हुए। अकादमिक समिति के सदस्यों में है संयुक्त सचिव (विस्तार) या उनकी नामिती, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, चार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, मैनेज कार्यकारी समिति के दो सदस्य, मैनेज के वरिष्ठ संकाय, और सहयोगी सदस्य/ विशेष अतिथि जिनमें नामी प्रबंध संस्थानों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, विस्तार शिक्षा निदेशालयों के निदेशक और कृषि विकास में अपना योगदान दिए व्यक्ति / वैज्ञानिक वर्ष 2019-2020 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं / प्रामाणित फार्म / पशुधन सलाहकार कार्यक्रमों के विवरण आगे दिया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 182 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 4761 भागीदारों ने भाग लिया। केन्द्र अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, फीड-दि-फ्यूचर भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण और प्रामाणित फार्म / पशुधन सलाहकार कार्यक्रम (सी एफ ए) के विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	केंद्र का नाम	आयोजित कार्यक्रम अप्रैल 2019 - मार्च 2020					कुल आयोजित कार्यक्रम	प्रति भागियों की संख्या
		प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यशाला	आरटीपी	एफटीएफ-आईटीटी	सीएफ एपी		
1	कृषि विस्तार नीति विस्तार में सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा कृषि विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता का केंद्र	09	02	-	11	-	22	558
2	कृषि विस्तार नवाचार, सुधार व कृषि उद्यमिता का केंद्र	14	04	19	-	-	37	1238
3	कृषि संस्थानों की क्षमता निर्माण का केंद्र	09	00	-	-	-	09	236
4	कृषि विस्तार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और विपणन का केंद्र	19	02	-	-	-	21	491
5	कृषि-संबद्ध क्षेत्र विस्तार का केंद्र	23	00	-	-	-	23	615
6	कृषि विस्तार में ज्ञान प्रबंधन, आईसीटी तथा मास मीडिया का केंद्र	20	00	-	-	-	20	449
7	कृषि में जेन्डर, पोषण सुरक्षा तथा शहरी कृषि का केंद्र	08	02	-	-	-	10	243
8	जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलन का केंद्र	09	02	-	-	13	24	579
9	सतत कृषि, कार्यक्रमों और योजनाओं के निगरानी व मूल्यांकन का केंद्र	14	02	-	-	-	16	351
योग :		125	14	19	11	13	182	4761
कुल योग:		182					182	4761

आरटीपी: रिफ्रेसर प्रशिक्षण कार्यक्रम; एफटीएफ-आईटीटी - फीड द फ्यूचर - भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण; सीएफएपी: प्रमाणित फार्म / पशुधन परामर्श कार्यक्रम.

I. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. फीड-दि-फ्यूचर भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

फीड-दि-फ्यूचर भारत त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफ टी एफ - आई टी टी) यू एस ए आई डी से निधीयन और मैनेज द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण 25 जुलाई 2016 को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का कार्यान्वयन 2016 - 2020 के दौरान 17 आफ्रीकी और आसियायी देशों के 1400 कार्यकारियों के लिए 44 प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा करना है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य चुने गए अफ्रीकी एवं आसियाई देशों में खाद्य व पौष्ठिक सुरक्षा में संस्थानात्मक व मानवीय दक्षता की कमियों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम अफगानिस्तान, काम्बोडिया, लाओ, पी डी आर, मियान्मार, मंगोलिया, वियतनाम, केन्या, मालावी, लाइबीरिया, घाना, युगांडा, रवान्डा, डेमोक्रटिक रिपब्लिक ऑफ कान्गो, मोजामबिक, टान्जानिया, सूडान और बोट्सवाना को कवर करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, एफ टी एफ - आई टी टी के कुल 10 कार्यक्रम आसिया और आफ्रीका क्षेत्र के 17 देशों के 257 प्रतिनिधि कार्यकारियों के लिए आयोजित किए गए है। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भारत के श्रेष्ठ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थानों और अन्य नामी संगठनों के सहयोग से किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण निम्नानुसार है।

1. "एग्रिबिजिनेस एण्ड मैनेजमेंट" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद में 18 जून से 2 जुलाई, 2019 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

2. "एग्रिबिजिनेस - स्टार्टअप टु स्केल अप" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद में 10-24 जुलाई, 2019 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

3. "जलवायु स्मार्ट कृषि" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज और आईसीएआर-क्रिडा, हैदराबाद, तेलंगाना में 20 अगस्त से 3 सितंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 27 अधिकारियों ने भाग लिया।

4. "उत्पादन हेतु समेकित तकनीक" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीएआर-सीटीसीआरआई, तिरुवनन्तपुरम, केरल में 16-30 सितंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 29 अधिकारियों ने भाग लिया।

5. "कृषि वानिकी: पॉलिसी, प्रैक्टीस और इम्पैक्ट" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर, नई दिल्ली में 10-24 अक्तूबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

6. "विकासशील देशों में मुख्य फसलों के नाशीकीट और रोग हेतु समेकित प्रबंधन रणनीति" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में 19 नवंबर से - 3 दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

7. "कृषि नीति निर्माण, पुनर्विचार और विश्लेषण" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में 21 जनवरी से - 4 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

8. "विकासशील देशों में सतत कृषि के लिए उत्तम कृषि अभ्यास" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इक्रिसेट (आईसीआरआईएसएटी), पटानचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना में 11-25 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 25 अधिकारियों ने भाग लिया।

9. "एग्रिप्रेन्यूरशिप के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य जोड़ तकनीक" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएफटीआरआई, मैसूर में 03-18 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 23 अधिकारियों ने भाग लिया।

10. "बागवानी फसलों में उत्पाद से फसलोत्तर प्रबंधन" पर एफ टी एफ - आई टी टी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यूएचएस, बगालकोट, कर्नाटक और यूएएस, बंगलूरु, कर्नाटक में 09-23 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 23 अधिकारियों ने भाग लिया।

2. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) प्रशिक्षण

प्रशिक्षण सततत कृषि विकास हेतु कृषि विस्तार दृष्टिकोण पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज, हैदराबाद में 17 से 30 सितंबर, 2019 तक आयोजित किया गया है। 13 विकासशील देशों के 21 भागीदार यथा बुरून्डी, कम्बोडिया, केन्या, कजकिस्तान, मलावी, मन्गोलिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, साऊथ सूडान, सूडान, तजिकिस्तान, टैन्जानिया और वियातनाम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भागीदारों में कृषि विस्तार में कंप्यूटर एप्लिकेशन के उपयोग का भारतीय अनुभव, कृषि विस्तार में आई सी टी एप्लिकेशन्स के नवीन और उभरती प्रवृत्तियों पर भागीदारों के प्रायोगिक ज्ञान को बढ़ाना, सततत कृषि विकास में आई सी टी के नवीन कार्यों की उपयोगिता के लिए प्रभावी विस्तार रणनीतियों की तैयारी में मदद करने पर भागीदारों के ज्ञान और समझ को बढ़ाना है।

II. महत्वपूर्ण कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियाँ:

पुनरावलोकन अवधि के दौरान मैनेज ने निम्न मुख्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया है।

- मैनेज में 18-19 फरवरी, 2020 के दौरान मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग में खाद्य व पौष्ठिक सुरक्षा की बढ़ोत्तरी और विकास के लिए कृषि विस्तार के रास्ते पर एम एस यू अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- "न्यू फ्रान्टारर्स इन एग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन (मैनेज-विश्वविद्यालय की मैत्री के भाग के रूप में और ए ई एस ए - क्रिस्प के सहयोग से)" मैनेज, हैदराबाद में 29-31 जुलाई, 2019 के दौरान किया गया जिसमें 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- "इन्नोवेटिव एक्सटेन्शन मैनेजमेंट फर अपलिफ्टिंग लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स-स्टेटस, इन्नोवेटिव्स एण्ड वे फारवर्ड" पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मद्रास वेटरनरी कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु में 27-28 जून, 2019 को 194 प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया।

- "डब्लिंग फार्मर्स इनकम: स्ट्रैटजीस फर ड्राइलैंड एग्रिकल्चर" पर 29 प्रतिनिधियों के लिए 18-19 नवंबर, 2019 के दौरान मैनेज, हैदराबाद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- "जेन्डर सेन्सिटाइजेशन एण्ड पॉलिसी एड्वोक्सी ऑफ जेन्डर फन्क्शनरीस" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन मैनेज, हैदराबाद में 5-6 दिसंबर, 2019 के दौरान 27 प्रतिनिधियों के लिए किया गया है।
- "डेसेट्रलाइजड एक्सटेंशन सिस्टम फॉर रैनफेड एग्रिकल्चर" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन मैनेज, हैदराबाद में 12-13 फरवरी, 2019 के दौरान 27 प्रतिनिधियों के लिए किया गया है।
- "ओरिएन्टिंग प्रोडक्शन एजेन्सीस टुवार्ड्स मार्केटिंग एक्सटेन्शन" पर राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन सह-कार्यशाला का आयोजन 25-26 फरवरी, 2020 को मैनेज में 16 प्रतिनिधियों के लिए किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षणों की एक झलक

III. **प्रमाणित फार्म/पशुधन सलाहकार कार्यक्रम**

एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि एवं अन्य क्षेत्र के विस्तार अधिकारियों के लिए आई सी ए आर संस्थाओं / राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य नामी संस्थाओं की सहायता से मैनेज ने 13 "फार्म / पशुधन सलाहकार" कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें तीन मॉड्यूलों को कवर किया गया यथा मॉड्यूल I क्षेत्र विशेष तकनीक (3 महीने); मॉडयूल -II आई सी ए आर संस्थानों अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (15 दिनों के लिए) में 20 फसल / उद्यमों पर गहन विशेष कौशल अभिमुख प्रशिक्षण और मॉड्यूल - III मेन्टार वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी समर्थन। वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित प्रमाणित फार्म / पशुधन सलाहकार कार्यक्रमों के विवरण निम्नानुसार है:

1. बीज तकनीक पर 23 सितंबर से 07 अक्तूबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। 15 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
2. जैविक कृषि (बैच- I) पर 10 - 24 अक्टूबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। 27 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3. चावल पर 10 - 24 अक्टूबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4. दलहन पर 10 - 24 अक्टूबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 14 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5. सब्जियों पर 10 - 24 अक्टूबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6. मसालों पर 11 - 25 नवंबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड, केरल में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7. फलों पर 12 - 26 नवंबर, 2019 तक आई सी ए आर - भारतीय फल अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8. भेड़ पर 21 नवंबर - 05 दिसंबर, 2019 तक आई सी ए आर - केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में प्रमाणित पशुधन सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

9. बकरियों पर 26 नवंबर - 10 दिसंबर,, 2019 तक आई सी ए आर - केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित पशुधन सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

10. मवेशियों पर 03 - 17 दिसंबर, 2019 तक आई सी ए आर - केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित पशुधन सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

11. पोल्ट्री पर 03 - 17 दिसंबर, 2019 तक आई सी ए आर - पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, तेलंगाना में प्रमाणित पशुधन सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

12. जैविक कृषि (बैच- II) पर 05 - 19 दिसंबर, 2019 तक आई सी ए आर - आई आई एफ एस आर, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 23 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

13. कदन्न पर 22 जनवरी - 05 फरवरी, 2020 तक आई सी ए आर - भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना में प्रमाणित फार्म सलाहकार का मॉड्यूल - II कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3. अनुसंधान और परामर्श

मैनेज कृषि विस्तार प्रबंधन में समकालीन विषयों पर अनुसंधान करता है। राज्य के विभागों और संस्थानों को परामर्श सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के अनुरोध पर मैनेज विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। पूर्ण कर लिए गए तथा चालू अनुसंधान और परामर्श अध्ययनों का विवरण नीचे दिया गया है:

पूर्ण कर लिए गए अध्ययन

1. **सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन - वर्ष 2019-20** (सतत कृषि, कार्यक्रम और योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का केंद्र)

   तेलंगाना के वरंगल जिले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ अध्ययन किए गए थे.

   शोध अध्ययन में भारत के तेलंगाना राज्य के एक गाँव में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जाँच की गई थी। केस स्टडी के लिए कुनकुदुपमुला गाँव को चुना गया था। गाँव के सभी घरों का सर्वेक्षण जनगणना के आधार पर किया गया था। ग्रामीणों को मिलने वाले लाभों का आकलन किया गया था और योजनाओं में सुधार के लिए नीतिगत सुझाव दिए गए थे। गाँव में परिवारों के बीच लगभग सात योजनाएँ जैसे मुफ्त बिजली, ऋण माफी, उर्वरक सब्सिडी, मनरेगा, पीडीएस, 'आसरा' पेंशन तथा गैस सब्सिडी प्रचलित हैं।

2. **भारत में कृषि बीमा को किसान - हितैषी और जलवायु अनुसार लचीला बनाना आगे का रास्ता** (कृषि विस्तार में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्र एवं विपणन)(सेंटर फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन)

   भारत में, कृषि उत्पादन के अनोखे स्वरूप को देखते हुए, फसल बीमा विशेष रूप से कमजोर वर्गों के किसानों (छोटे और मझौले किसानों) तथा सामान्य रूप से कृषि के अन्य श्रेणियों से दूर रहा है। समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं में सुधार करने के पहल के बावजूद, भारत में कृषक समुदाय के बीच जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने वाला यह तंत्र असफल रहा है। इसके बावजूद, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आरंभ किया, जो कृषि-व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक नया संस्करण है। इस योजना को पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं के तात्कालिक संस्करण के रूप में माना जाता है, जो अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली फसल की हानि/क्षति के संदर्भ में सहायता प्रदान करता है, किसानों की आय को स्थायित्व प्रदान करता है, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। इस अध्ययन ने भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न फसल बीमा योजनाओं का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया। इसके अलावा, रिपोर्ट में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रदर्शन की तुलना पहले की फसल बीमा योजनाओं के साथ भी की गई है।

3. **शहरी खेती का घरेलू विश्लेषण: खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रणनीति** (कृषि में लिंग, पोषण सुरक्षा और शहरी कृषि का केंद्र) (सेंटर फॉर जेंडर इन एग्रीकल्चर, न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन एग्रीकल्चर) अनुसंधान के उद्देश्य थे: उत्तरदाताओं की प्रोफाइल का अध्ययन करना; उत्तरदाताओं के बीच शहरी खेती के अभ्यास का विश्लेषण; 'शहरी खेती' के माध्यम से मिलने वाली खाद्य सुरक्षा की सीमा को तय करना और इस अभ्यास को अपनाने में उत्पन्न बाधाओं का पता लगाना।

   निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकतर उत्तरदाता (43%) खाद्य समूहों जैसे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जियां और औषधीय पौधों की 2 से 4 किस्मों की खेती करते थे। उनमें से अधिकांश (45%) अपने घरों में कम से कम 1 से 5 प्रकार के फल और सब्जियां उगा रहे थे। परिणामों से पता चलता है कि शहरी खेती करने का प्राथमिक कारण उनकी अपनी रुचि, जुनून, पृष्ठभूमि (कृषि परिवार से होना) था तथा अपने परिवार के लिए जैविक भोजन पैदा करना था। शहरी खेती करने वालों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याएं कीटों, पक्षियों और बंदरों (26%) से उत्पन्न होने वाले खतरे थे तथा साथ ही गुणवत्ता वाले बीजों (17%) का न मिलना भी था.

4. **मैनेज द्वारा अपनाए गए गाँव में ग्रामीण परिवार के भोजन और पोषण सुरक्षा का मूल्यांकन** (कृषि में लिंग, पोषण सुरक्षा और शहरी कृषि का केंद्र) (सेंटर फॉर जेंडर इन एग्रीकल्चर, न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन एग्रीकल्चर)

   अनुसंधान के उद्देश्य थे: उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन करना; उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली पाक विधियों का अध्ययन करना; चयनित उत्तरदाताओं के भोजन आदतों को समझना; उत्तरदाताओं की खाद्य और पोषण सुरक्षा का मूल्यांकन करना।

   मैनेज द्वारा अपनाए गए गांव अर्थात भारत के तेलंगाना राज्य के मोइनाबाद मंडल के अंतर्गत रंगा रेड्डी जिले के श्रीरामनगर से उत्तरदाताओं के रूप में सौ ग्रामीण महिलाओं को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। अध्ययन का सामान्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना था। यह अध्ययन ग्रामीण घरों की विशिष्ट भोजन आदतों और खाना पकाने के पद्धतियों का मूल्यांकन करने और निष्कर्षों के माध्यम से परिलक्षित विभिन्न आहार व्यवहारों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया गया था। उत्तरदाताओं के भोजन आदतों में दूध, मांस, मछली और फलों की खपत कम थी। उनके द्वारा सामान्यतया सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली खाना पकाने की विधियाँ थीं - स्टीमिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग और डीप फ्राईंग। उनके भोजन खपत में ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम और लौह अनुशंसित मात्रा में नहीं होता था। अत: भोजन खपत के पैटर्न के बारे में उनके ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए उन्हे प्रशिक्षण देना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए अंतःक्षेप कार्यक्रमों को आयोजित करना आवश्यक है।

जारी अध्ययन

5. **किसानों को बाजारों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने वाले मॉडलों का मूल्यांकन:** तेलंगाना राज्य में सिद्दिपेट राइतु बाजार (किसान बाजार) का एक मामला (कृषि विस्तार में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं विपणन केंद्र)

   तेलंगाना राज्य में किसानों को बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाले मॉडल के तहत सिद्दिपेट राइतु बाजार (किसान बाजार) का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य राज्य में किसान-

बाजारों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना; किसान-बाजार की बुनियादी पहलुओं जैसे बुनियादी अवसंरचना निर्माण, गतिविधियों का प्रवाह और मूल्य खोजी तंत्र का विश्लेषण करना; रायथू बाजार में किसानों की भागीदारी के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करना, इस मॉडल के अंतर्गत निर्माताओं और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों और बाधाओं पर उनकी धारणा को समझना तथा किसान-बाजारों के सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना एवं सुझाव देना। समीक्षा कार्य, हितधारकों के साथ वार्ता और प्रश्नावली तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

6. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ताप लहर (हीटवेव) प्रबंधन: ताप लहर (हीट देव) दिशानिर्देशों तथा ताप लहर कार्य योजना की प्रभावकारिता।** (जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन केंद्र) (सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एडाप्टेसन)

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी द्वारा इस परियोजना को मैनेज को सौंपा गया है। इस अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य विभागों में राज्य ताप लहर कार्य योजना के विभिन्न घटकों और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना; आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के चयनित जिलों में कृषि और पशुधन सहित मृत्यु दर और परिसंपत्ति हानि के संदर्भ में ताप लहर की प्रकृति और जोखिम का विश्लेषण करना; आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में वहां की आबादी द्वारा अपनाई जा रही जोखिम शमन रणनीति का पता लगाना; चयनित जिलों में जोखिम को कम करने में राज्य ताप लहर कार्य योजना की प्रभावकारिता का विश्लेषण करना और प्रभावी रूप से कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देना है। आंध्र प्रदेश के चार जिलों और तेलंगाना के चार जिलों को डेटा संग्रह के लिए चुना गया था। विभिन्न लाइन विभागों के साथ जिला स्तरीय बैठकें सात जिलों में पूरी कर ली गई हैं तथा डेटा संग्रह जारी है।

7. **भारत में, विशेष रूप से तेलंगाना के संदर्भ में प्रमुख कृषि-वस्तुओं की घरेलू और निर्यात प्रतिस्पर्धा** (कृषि विस्तार में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं विपणन केंद्र)

इसका उद्देश्य चयनित वस्तुओं के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि का विश्लेषण करना; तेलंगाना राज्य से चयनित वस्तुओं की घरेलू और निर्यात प्रतिस्पर्धा दोनों का विश्लेषण करना; तथा अखिल भारतीय स्तर पर चयनित वस्तुओं के व्यापार की दिशा का विश्लेषण करना था। समीक्षा कार्य, डेटा संग्रह, हितधारकों के साथ वार्ता और डेटा विश्लेषण का कार्य पूर्ण हो गया है। रिपोर्ट लेखन कार्य जारी है।

8. **शहरी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए माइक्रो-ग्रीन को बढ़ावा देना** (राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद के सहयोग से सेंटर फॉर जेंडर इन एग्रीकल्चर, न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन एग्रीकल्चर)

अध्ययन का उद्देश्य केंद्र में विभिन्न माध्यमों में व्यापक 'माइक्रो-ग्रीन' की खेती करना; विभिन्न माध्यमों में पैदा किए गए चयनित 'माइक्रो-ग्रीन' की पोषण संबंधी संरचना का विश्लेषण और तुलना करना; 'माइक्रो-ग्रीन' का उपयोग करके व्यंजनों या उत्पादों का विकास करके मानकीकृत करना; चयनित विषयों पर 'माइक्रो-ग्रीन' के चिकित्सीय प्रभाव का अध्ययन करना; शहरी जनता के बीच 'माइक्रो-ग्रीन' की खेती के बारे में जागरूकता पैदा करना और बढ़ावा देना था।

इस अध्ययन के अंतर्गत, माइक्रो-ग्रीन के उत्पादन के लिए चार अलग-अलग माध्यमों में 10 किस्म के बीज उगाए गए थे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) पर नमूनों की पोषण संरचना (दो प्रतियों में 40

नमूनों) का विश्लेषण किया गया था। अधिकांश नमूनों का विश्लेषण उनकी पोषण संबंधी संरचना के लिए किया गया था। प्रमुख घटक के रूप में माइक्रो-ग्रीन का उपयोग करते हुए दस व्यंजनों को विकासित किया गया, उनका संवेदी मूल्यांकन एवं मानकीकरण किया गया और एनआईएन पर विश्लेषण के लिए दिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार है।

परामर्श

1. **एफएओ - मैनेज पोषण संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए मैनेज की परामर्शदात्री परियोजना -** भारत में कृषि कृषि विस्तार सलाहकार सेवा (ईएएस) प्रदाताओं के प्रशिक्षण में पोषण का एकीकरण (कृषि में लिंग-भेद,पोषण सुरक्षा एवं शहरी कृषि केंद्र) (सेंटर फॉर जेंडर इन एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन एग्रीकल्चर)

   प्रमुख गतिविधियाँ हैं - कृषि विस्तार सलाहकारी सेवा (ईएएस) प्रदाताओं के लिए पोषण पर प्रशिक्षण पैकेज विकसित करना; पायलट परीक्षण तथा निष्कर्षों के अनुसार प्रशिक्षण पैकेज को संशोधित करना और उनके पाठ्यक्रम में पैकेज के संस्थानीकरण के लिए एक रोड मैप विकसित करना।

2. **सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के ज्ञान का मूल्यांकन और प्रमाणन - कृषि से आजीविका (सीआरपी-एलएच) – एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार** (कृषि विस्तार नवाचार, सुधार एवं कृषि-उद्यमिता केंद्र) (सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इनोवेशन,रिफॉर्म एंड एग्रीप्रेन्योरशिप)

   ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार जून 2011 से दीनदयाल अंत्योदया योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे- एनआरएलएम) को साकार करने में लगी है। एनआरएलएम मिशन सामुदायिक पेशेवरों अर्थात (i) पशु सखियों और (ii) कृषि सखियों के माध्यम से सतत् आजीविका के संवर्धन में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

   सीआरपी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, डे-एनआरएलएम मिशन सभी प्रशिक्षित सीआरपी को ज्ञान मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की प्रणालियों में शामिल करना चाहता है। सीआरपी - फार्म आजीविका ज्ञान मूल्यांकन और प्रमाणन प्रोटोकॉल की संस्थापना के लिए मैनेज नोडल एजेंसी है।

   अप्रैल, 2019 से लेकर, मैनेज की मुख्य गतिविधियाँ हैं- डे-एनआरएलएम पर इन्सेप्शन रिपोर्ट तैयार करना, पाठ्यक्रम सामग्री और स्कोर कार्ड की डेस्क समीक्षा करना और मूल्यांकन करने के लिए टैब-आधारित एप्लिकेशन/मॉड्यूल तैयार करना, सीआरपी ग्रेडिंग और मूल्यांकन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना, स्थानीय संसाधन व्यक्तियों (मूल्यांकनकर्ताओं) की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना तथा उनका नामांकन करना। कृषि सखी और पशु सखी के लिए छह भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में एक मास्टर प्रश्न बैंक संकलित किया गया था। शोलापुर जिले में पायलट अध्ययन पूरा हो गया है तथा महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में कार्य प्रगति पर है। मैनेज, हैदराबाद में 10 और 11 फरवरी, 2020 को सीआरपी प्रमाणीकरण के लिए पद्धति और प्रश्नावली पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने तथा संस्थागत व्यवस्था और आजीविका हेतु प्रशिक्षण पर स्थानीय संसाधन व्यक्तियों (एलआरपी) के लिए दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।

3. **यूएनडीपी दिशा - एक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड (एएलसी) बिजनेस एंटरप्राइज लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए ज्ञान और आकलन भागीदार के रूप में मैनेज** (कृषि विस्तार नवाचार, सुधार एवं कृषि-उद्यमिता केंद्र) (सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इनोवेशन,रिफॉर्म एंड एग्रीप्रेन्योरशिप)

महान समुदायों का निर्माण करने और ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाने के लिए, एक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड (एएलसी इंडिया) ने दिशा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से भारत में महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के सृजन के लिए बिजनेस एंटरप्राइज लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम की पहल की है। कार्यक्रम के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए मैनेज ने एएलसी और यूएनडीपी - दिशा के साथ सहभागिता की है। छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मैनेज द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएँ इस प्रकार हैं: प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक भागीदार के रूप में कार्य करना और मूल्यांकन ढांचे के विकास में एएलसी इंडिया के साथ सहयोग करना तथा एएलसी इंडिया के साथ समन्वय करना एवं 100 बिजनेस लीडरों के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन का संचालन करना।

कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैनेज ने 100 ग्रामीण महिलाओं हेतु फाइनल मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए मूल्यांकन मॉडल तैयार कर लिया था। मूल्यांकन रिपोर्ट यूएनडीपी और एएलसी को प्रस्तुत की गई थी। नगनपल्लि (तेलंगाना), अमेठी (यूपी), गोंदिया (महाराष्ट्र) और कालाहांडी (ओडिशा) में महिला उद्यमिता कार्यक्रम (डब्ल्यूईपी) का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सितंबर, 2019 से अप्रैल, 2020 तक के कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है।

4. **सतत आजीविका पर एनआईआरडी एवं पीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन तथा सीआरपी और एनआरपी के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन (एसएलएसीसी)** (कृषि विस्तार नवाचार, सुधार एवं कृषि-उद्यमिता केंद्र) (सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इनोवेशन,रिफॉर्म एंड एग्रीप्रेन्योरशिप)

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र [सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट (सीएनआरएम)] ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज) में 200 से अधिक सीआरपी (सामुदायिक संसाधन व्यक्ति/कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) और 100 एनआरपी (प्राकृतिक संसाधन व्यक्ति/ नेचुरल रिसोर्स पर्सन) / मिशन कर्मचारियों को शामिल करते हुए "सतत आजीविका एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन" (सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज) (एसएलएसीसी) पर एक प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया है।

इस कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में मैनेज की भूमिका एक तीसरे पक्ष की है। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर 297 प्रतिभागियों (सीआरपी और एनआरपी / मिशन कर्मचारियों) के लिए प्री और पोस्ट मूल्यांकन किया गया था, जिसमें से 292 प्रतिभागी प्रमाणित किए थे। वे उम्मीदवार जो मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम थे (जिन्होंने पोस्ट मूल्यांकन में 40% से अधिक प्राप्त किया) को मैनेज द्वारा प्रमाणित किया गया। सीआरपी बैच के लिए हिंदी में अलग-अलग प्री और पोस्ट प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे।

4. योजनाएं

एग्रि क्लिनिक्स एवं एग्रि बिजिनेस केंद्र योजना (एसी व एबीसी)

परिचय

भारत सरकार ने कई कार्यों को प्रारंभ किया और देश में उद्यमिता की संस्कृति को गति प्रदान करने के लिए नीति निर्माण किया। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ने कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कई अवसर एवं नए कार्यक्रमों का सृजन किया है। एग्रि क्लिनिक्स और एग्रि बिजिनेस केन्द्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो युवा एग्रि व्यावसायिकों में कृषि-उद्यमिता कौशल को विकसित करने उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। अप्रैल 2002 में इसके आरंभ से लेकर अबतक इस योजना ने कई कृषि उद्यमियों को अपने खुद का व्यापार प्रारंभ करने में सफलता प्रोत्साहन दिया।

मैनेज देश भर के 140 नोडल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने-अपने राज्य में कृषि एवं तत्संबंधी विज्ञान / लाईफ साईन्सेस डिप्लोमा धारकों एवं माध्यमिकी में उत्तीर्ण हुए आवेदकों को दो महीने का नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । प्रशिक्षण के बाद, कृषि उद्यम स्थपित करने के लिए प्रशिक्षित आवेदकों को एक वर्ष तक हैंडहोल्डिंग समर्थन दिया जाता है। प्रिशिक्षित को स्टार्ट-अप लोन और क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड कम्पोजिट सब्सिडी बैंकों एवं नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एग्रि क्लिनिक्स और एग्रि बिजिनेस केंद्र योजना की मुख्य भूमिका स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और कृषि सहलाहकारी सेवा सस्ते में प्रदान करना हैं । प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 72,754 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। और 28,755 उद्यमों की स्थापना के साथ 39.53% की सफलता दर हासिल किया गया। अगस्त 2019 से प्रशिक्षण अवधि दो महीने के बजाय 45 दिन है।

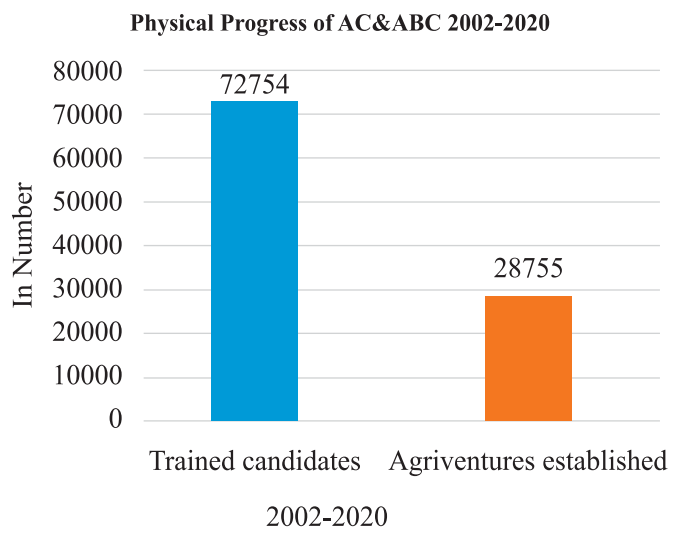

प्रशिक्षण नेटवर्क

भारत के 28 राज्यों में 140 एन टी आई के साथ किया गया समझौते का ज्ञापन		
1.	गैर सरकारी संगठनों	76
2.	राज्य सरकार के संस्थान	12
3.	राज्य के कृषि विश्वविद्यालय	16
4.	कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)	17
5.	आत्मा, समेति	4
6.	सहकारी प्रबंधन संस्थान	4
7.	कृषि व्यवसाय कंपनियाँ	4
8.	आईसीएआर संस्थान	3
9.	अन्य विश्वविद्यालय	4
	संपूर्ण	140

प्रशिक्षण अवधि : 45 Days

Training Module:
http://www.agriclinics.net/schemetraining.html

भारत में एसी एवं एबीसी योजना की प्रगति: वर्ष 2019-20 के दौरान 6955 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 140 (एन टी आई) के माध्यम से किया गया है।

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	206
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	21
4.	बिहार	123
5.	चंडीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ	132
7.	दिल्ली	3
8.	गोवा	0
9.	गुजरात	161
10.	हरियाणा	25
11.	हिमाचल प्रदेश	1
12.	जम्मु और कश्मीर	0
13.	झारखंड	24
14.	कर्नाटक	172
15.	केरल	16
16.	मध्य प्रदेश	759
17.	महाराष्ट्र	2293
18.	मणिपुर	33
19.	मेघालय	1
20.	मिजोरम	1
21.	नागालैंड	0
22.	ओडीशा	22
23.	पॉण्डीचेरी	4
24.	पंजाब	10
25.	राजस्थान	338
26.	सिक्किम	0
27.	तमिलनाडु	151
28.	तेलंगाना	759
29.	त्रिपुरा	0
30.	उत्तर प्रदेश	1636
31.	उत्तरांचल	36
32.	पश्चिम बंगाल	27
	कुल	6955

राज्यवार प्रशिक्षुओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	18222
2.	उत्तर प्रदेश	16032
3.	तमिलनाडु	7894
4.	कर्नाटक	4151
5.	बिहार	4078
6.	मध्य प्रदेश	4043
7.	राजस्थान	3833
8.	गुजरात	2065
9.	तेलंगाना	1793
10.	जम्मु और कश्मीर	1491
11.	आंध्र प्रदेश	1373
12.	पश्चिम बंगाल	1190
13.	छत्तीसगढ	905
14.	झारखंड	771
15.	असम	756
16.	हरियाणा	721
17.	पंजाब	666
18.	ओडीशा	625
19.	उत्तरांचल	506
20.	मणिपुर	472
21.	हिमाचल प्रदेश	422
22.	केरल	239
23.	नागालैंड	184
24.	पॉण्डीचेरी	139
25.	दिल्ली	37
26.	मेघालय	36
27.	अरुणाचल प्रदेश	35
28.	मिजोरम	35
29.	गोवा	13
30.	सिक्किम	9
31.	त्रिपुरा	5
32.	चंडीगढ़	4
	कुल	**72754**

राज्यवार स्थापित कृषि उद्योग की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	8155
2.	उत्तर प्रदेश	7152
3.	तमिलनाडु	3689
4.	कर्नाटक	1619
5.	मध्य प्रदेश	1475
6.	बिहार	1392
7.	राजस्थान	1387
8.	गुजरात	767
9.	तेलंगाना	422
10.	छत्तीसगढ	335
11.	आंध्र प्रदेश	321
12.	पश्चिम बंगाल	296
13.	हरियाणा	234
14.	असम	227
15.	पंजाब	218
16.	जम्मु और कश्मीर	191
17.	झारखंड	186
18.	उत्तरांचल	161
19.	मणिपुर	128
20.	ओड़ीशा	114
21.	हिमाचल प्रदेश	108
22.	पॉण्डीचेरी	84
23.	केरल	51
24.	नागालैंड	21
25.	गोवा	7
26.	दिल्ली	6
27.	अरुणाचल प्रदेश	3
28.	मेघालय	3
29.	चंडीगढ़	1
30.	सिक्किम	1
31.	त्रिपुरा	1
32.	मिजोरम	0
	कुल	**28755**

कार्यशाला / सेमिनार / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी

एसी और एबीसी योजना पर नाबार्ड संवेदीकरण कार्यशालाएं

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक [नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड)] द्वारा भारत सरकार के सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और बैंकरों को एसी और एबीसी योजना की मुख्य विशेषताओं पर संवेदीकरण करने के लिए भारत सरकार की एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिज़नेस केंद्रों के स्कीमों पर एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मैनेज के प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित नाबार्ड संवेदीकरण कार्यशालाओं में भाग लिया। इस कार्यशाला में शामिल होने वाले मुख्य भागीदार थे-नाबार्ड कर्मचारी, एमओए व एफडब्ल्यू (MoA & FW) से प्रतिनिधि, मैनेज, जिला कृषि अधिकारी, जिलों में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई), सफल कृषि उद्यमी और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि। एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत क्रेडिट-लिंकेज के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और सुझावों को नोट किया गया। नाबार्ड-क्षेत्रिय कार्यालय पर विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझाए गए कुछ सुझावों को सूचीबद्ध कर प्रसारित भी किया गया।

एसी और एबीसी योजना पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकें

एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस केंद्र योजना की बैंक संबंधित ऋण और सब्सिडी प्रसंस्करण मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करने और उन पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं। मैनेज के प्रतिनिधियों ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में आयोजित बैठकों में भाग लिया। बैठक में नाबार्ड के कर्मचारी, प्रमुख बैंक पदाधिकारी, मैनेज, जिला कृषि अधिकारी, जिलों में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई), सफल कृषि-उद्यमी और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत क्रेडिट-लिंकेज के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और सुझावों को नोट किया गया। विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझाए गए कुछ सुझावों को सूचीबद्ध कर प्रसारित किया गया.

पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम: कौशल को सुदृढ़ करना

कृषि-उद्यमियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी) का उद्देश्य प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का पालन करवाना, उसे ताज़ा करना और विस्तारित करना है। मैनेज ने एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस केंद्र (एसी व एबीसी) योजना के अंतर्गत संस्थापित कृषि-उद्यमियों के लिए लगभग 20 थीम

आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन किए। भारत में आरटीपी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय भागीदार बन गए। इनमें से कुछ हैं - राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (रा व स्वा प्र सं), कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय (डीपीआर), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद, तेलंगाना; राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल, हरियाणा, आईसीएआर-सीआईएसएच लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एसआईएईटी, भोपाल, मध्य प्रदेश, समेती(एसएएमईटीआई), उत्तर प्रदेश, वनामती, नागपुर और पुणे, महाराष्ट्र, केवीके कोल्हापुर II महाराष्ट्र, एसीआरओ कुडमियानमलई तमिलनाडु, एबीडी- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (एबीडी - टीएनएयू) और आईसीएआर-सीआईएई, कोयम्बतूर, तमिलनाडु, कर्नाटक। वर्ष 2019-20 को दौरान 19 पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 539 कृषि-उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया और कृषि-उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए उनके अनुभवों को फिर से तरो-ताजा किया गया।

वैश्विक किसान कृषि एक्सपो में कृषि-उद्यमि: फ्रंटियर कृषि-प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन

कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव पुणे- II ने कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार, एटीएमए, एनएचबी, नाबार्ड, मैनेज,आरसीएफ लिमिटेड, जिला परिषद, पुणे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीडीसीसी बैंक, पुणे, श्री. विग्र सहकारी चीनी कारखाना एवं भीम शंकर सहकारी चीनी कारखाना तथा मीडिया पार्टनर सहयाद्री दूरदर्शन, आकाशवाणी पुणे के सहयोग से 9 से 12 जनवरी 2020 के दौरान ग्लोबल फार्मर्स-लाइव डेमो, कृषि प्रदर्शनी और सम्मेलन ट्रेड नाम से कृषि प्रौद्योगिकी सप्ताह का आयोजन किया। 90000 से अधिक किसानों, छात्रों, विस्तार कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। केवीके के वसुंधरा फार्म की 80 एकड़ जमीन पर लाइव प्रदर्शन करते हुए 112 फसलों की किस्में उगाई गईं। 22 गुलदाउदी किस्में, पोषण संवेदी किचन गार्डन, रंगीन शिमला मिर्च की संरक्षित खेती और ककड़ी के लाइव प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। किसानों ने टोफू तैयार करने, एजोला, हाइड्रोपोनिक्स, हाइब्रिड नेपियर, हाड्गा, मक्का सहित सिलेज, दुधारू पशुओं के लिए लूस आवास प्रणाली, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर), यूरिया ब्रिकेट की तैयारी, वर्मी-कम्पोस्ट, दुग्ध प्रसंस्करण, दाल मिल, मोबाइल राइस मिल, स्पाइरल सेपेरेटर आदि विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों से जानकारी प्रप्त की। इसमें छह कृषि-उद्यमी अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करने और अपनी उपज का विपणन करने के लिए शामिल हुए।

कृषक में कृषि-उद्यमी: फ्रंटियर कृषि-प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन

कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती एक जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली की संबद्धता में कृषि विकास ट्रस्ट बारामती जिला, पुणे में स्थापित किया गया है। कृषि विकास ट्रस्ट के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने 16 से 19 जनवरी, 2020 के दौरान एक लाइव प्रदर्शन और कृषि एक्सपो कृषक-2020 का आयोजन किया। कृषि क्षेत्र की संपूर्ण वैल्यू चेन अर्थात खेती, प्रसंस्करण, संरक्षण, गुणवत्ता प्रबंधन, वितरण तथा बीमा सेवाओं से व्यापक प्रोफ़ाइल के साथ देशभर से प्रदर्शकों की तीन लाख से अधिक आगंतुकों ने 110 एकड़ में फैले इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में भाग लिया।

मैनेज ने इस कार्यक्रम में संस्थान की पहलों, एसीएबीसी गतिविधियों और इन्कुबेरान केंद्र को प्रदर्शित करने के लिए भाग लिया। एसीएबीसी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित चार कृषि-उद्यमियों ने एक्सपो में भाग लिया तथा अपने नवाचारों और सेवाओं को प्रदर्शित किया।

राष्ट्रीय घटनाओं/कृषि-प्रदर्शनी में भागीदारी

मैनेज ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) और आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित चार दिवसीय "14 वें कृषि विज्ञान कांग्रेस - 2019" में भाग लिया। मैनेज द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परामशी कार्यक्रमों और योजनाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत और साझा किया गया। मैनेज ने किसानों के लाभ के लिए उनके उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए एसी व एबीसी योजना के माध्यम से चयनित कृषि-उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। कांग्रेस ने अपनी थीम "कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए नवाचार" के साथ आगंतुकों को कृषि संकट को कम करने और किसानों के कल्याण में सुधार हेतु उनकी आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के बारे में सीखने और जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट, सीईडी, आंध्र प्रदेश में एक चिकित्सा शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनस केंद्र (एसी व एबीसी) योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कृषि उद्यमिता के परिप्रेक्ष्य को उद्धृत किया जो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला और पोषण सुरक्षा में क्रांति लाने के लिए अभिनव तरीके विकसित करता है। उन्होंने एसी व एबीसी योजना के प्राथमिक उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला जिसे केंद्र सरकार ने बेरोजगार कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें भविष्य के उद्यमियों के रूप में बदलने के लिए के लिए आरंभ किया है.

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकय्या नायडू द्वारा मैनेज के संकाय के साथ चर्चा

मैनेज के स्टाल पर तेलंगाना के माननीय राज्यपाल और उप-कुलपति, पी जे टी एस ए यू

मैनेज ने 21 और 22 अक्टूबर, 2019 के दौरान प्रो.जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू), हैदराबाद में आयोजित "दक्षिण भारत में व्यवसाय-उन्मुख कृषि के मशाल के रूप में युवा" पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया और अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन किया। तेलंगाना के माननीय राज्यपाल डॉ.तामिलीसाई सुंदरराजन ने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्रीमती वी. उषा रानी, आईएएस, महानिदेशक ने उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉ. सरवणन राज, निदेशक (कृषि विस्तार) तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैनेज - सीआईए ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आरकेवीवाई-रफ्तार(RKVY- RAFTAAR) योजना के अंतर्गत एग्री-स्टार्ट अप के लिए अवसरों की जानकारी दी। 500 से अधिक आगंतुकों ने मैनेज स्टॉल का दौरा किया। डॉ. तामिलीसाई सुंदरराजन, माननीय राज्यपाल, तेलंगाना, उप कुलपति, पीजेटीएसएयू तथा महानिदेशक, इक्रिसेट (आई सी आर आई एस ए टी) ने भी मैनेज स्टॉल का दौरा किया।

एक्वा क्लिनिक और एक्वा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एसी व एडीपी)

एक्वा क्लीनिक और एक्वा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एसी व एडीपी) बेरोजगार मत्स्य पालन करने वालों और संबद्ध विषयों में स्नातक तथा डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद द्वारा प्रायोजित एक माह का मुफ्त आवासीय कौशल विकास प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है। एसी व एडीपी में उद्यमिता विकास का प्रमुख उद्देश्य एक्वाकल्चर किसानों के लिए नए और अभिनव तकनीकों को आरंभ करना है तथा एक्वा वन केंद्रों (एओसी) की स्थापना करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

कार्यक्रम को वर्ष 2018-19 में अनुमोदित किया गया था और बाद में 300 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने हेतु मैनेज के लिए 10 कार्यक्रम स्वीकृत किए गए थे। प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए 130.50 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। 300 प्रतिभागियों में से, 288 को 10 नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के समन्वय में प्रशिक्षित किया गया। सफलता को देखते हुए, मैनेज पर एक बार फिर विचार किया गया और 30 एसी व एडीपी कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 405 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें मैनेज द्वारा अनुमोदित मत्स्य पालन नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से 900 बेरोजगार मत्स्य और संबद्ध विषय स्नातकों को प्रशिक्षित किया गया। 31 मार्च, 2020 तक मैनेज ने सफलतापूर्वक 16 कार्यक्रमों को पूरा किया और 478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

एनटीआई का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	एनटीआई की संख्या	राज्य	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	कॉलेज ऑफ फिशरीज, राहा, एएयू	असम	30
2	कॉलेज ऑफ फिशरीज, लेम्बुचेर्रा, सीएयू	त्रिपुरा	23
3	फिशरीज रिसर्च स्टेशन (एफ आर एस), पलायर	तेलंगाना	35
4	जबलपुर मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, एन डी वी एस यू,	मध्य प्रदेश	30
5	फ़िशकोपेड, भुवनेश्वर केंद्र	ओडिशा	36
6	मत्स्य महाविद्यालय, रत्नागिरी	महाराष्ट्र	24
7	डब्ल्यू बी यू ए एफ एस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	25
8	मुठथुकुर मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, एस वी वी यू,	अरुणाचल प्रदेश	31
9	मत्स्य अनुसंधान स्टेशन (एफआरएस), उन्डि	आंध्र प्रदेश	35
10	डॉ.एम जी आर फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च संस्थान, टीएनजेएफयू, पोंन्नेरी	तमिलनाडु	30
11	कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइन्स एण्ड टेक्नॉलजी (सीयूएसएटी), कोचिन	केरल	32
12	मत्स्य पॉलिटेक्निक, एसवीवीयू, बवेदेवरपल्लि	आंध्र प्रदेश	30
13	मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा	छत्तीसगढ़	30
14	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी (एसआईएफटी), काकिनाडा	आंध्र प्रदेश	28
15	समुद्री जीवविज्ञान, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, पारंगीपेट्टई	तमिलनाडु	36
16	आईसीएआर- सीआईएफई कोलकाता सेंटर	पश्चिम बंगाल	23
		कुल	**478**

2. एक्वा वन सेंटर (एओसी)

एक्वा वन सेंटर (एओसी) एक आईसीटी सक्षम एक्वाकल्चर सेवा केंद्र है। यह सलाहकार और तकनीकी सेवाएं, प्रयोगशाला परीक्षण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जैसी सेवाएं प्रदान करके किसानों की सहायता करता है और कृषि इनपुट आपूर्ति प्रदान करता है। एनएफडीबी रियायती स्कीम के अंतर्गत एक एओसी की इकाई लागत 20.00 लाख रुपए है।

मैनेज –सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप (सीआईए) को एक्वा वन केंद्रों (एओसी) की संस्थापना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्रस्तावित किया गया था। प्रतिभागियों को एसी व एडीपी केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। एक्वा वन केंद्र (एओसी) की 60 इकाइयों के लिए स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त हुआ। वर्ष 2019 के दौरान एनएफडीबी ने मत्स्य पालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के सीएसएस नीली क्रांति दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी दर को संशोधित करके सामान्य वर्ग के लिए 24% (4.80 लाख रुपए) और महिलाओं तथा एससी/एसटी वर्ग के लिए 36% (7.2 लाख रुपए) कर दिया गया। राज्य वार मंजूर किए गए एक्वा वन केंद्र (एओसी) नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	एओसी की सं.
1	आंध्र प्रदेश	5
2	बिहार	5
3	हरियाणा	1
4	कर्नाटक	7
5	केरल	1
6	मध्य प्रदेश	5
7	मणिपुर	2
8	ओडीशा	1
9	तमिलनाडु	9
10	तेलंगाना	3
11	त्रिपुरा	1
12	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	**44**

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं व अन्य आयोजन:

1. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, एनडीवीएसयू, जबलपुर, मध्य प्रदेश में 19-22 अगस्त, 2019 के दौरान "मत्स्यपालन एवं एक्वाकल्चर तथा मछली और मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन के उद्यमिता विकास" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 35 बेरोजगार युवाओं और मत्स्यपालन स्नातकों ने भाग लिया।

2. मछली प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी विभाग, मत्स्यपालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय केरल (केयूएफओएस), पाननगढ़, कोच्चि, केरल में 2-6 मार्च, 2020 के दौरान "मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी एवं मछली और मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन के उद्यमिता विकास" पर मैनेज – केयूएफओएस (KUFOS) सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 40 बेरोजगार महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया।

3. मैनेज ने 09-21 जून, 2019 के दौरान हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा आयोजित हिंद महासागर ट्यूना आयोग (आईओटीसी) की 23 वें वार्षिक सत्र (वर्ष 2019) और उसकी संबंधित बैठकों में भाग लिया। मैनेज ने एनएफडीबी, हैदराबाद में 10 जुलाई, 2019 को आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस समारोह में भी भाग लिया।

4. इस संस्थान ने 27 जुलाई 2019 को स्मार्ट एग्रीपोस्ट, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (एनएसीएसए), एमपीईडीए, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के सहयोग से विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आयोजित "मत्स्यपालन एवं एक्वाकल्चर में प्रभावी मूल्य श्रृंखला" कार्यशाला में भाग लिया।

5. मैनेज - सीआईए ने एसी व एडीपी एवं एओसी की मत्स्यपालन गतिविधियों में भाग लिया और अपना प्रदर्शन किया तथा "समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)" द्वारा हाईटेक्स प्रदर्शनीकेंद्र, हैदराबाद में 30 अगस्त से 1 सितंबर 2019 तक आयोजित "एक्वा एक्वरिया इंडिया पर राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी- 2019" के दौरान राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार (एनईए) - 2019 और आरकेवीवाई-रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) कार्यक्रम को संयुक्त रूप से प्रोमोट किया। महामहिम श्री वेंकैया नायडू, माननीय उपराष्ट्रपति,भारत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा श्रीमती वी. उषा रानी, आईएएस, पूर्व महानिदेशक, मैनेज और डॉ. सरवणन राज, निदेशक (कृषि विस्तार) इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।

6. मैनेज ने 28 सितंबर, 2019 के दौरान अमलापुरम, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश में आयोजित "18 वीं एक्वा-टेक - एक्सपो" में एसीएडीपी व एओसी, आरकेवीवाई-रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) कार्यक्रमों की मत्स्य गतिविधियों का प्रदर्शन किया और प्रस्तुती करण दिया। श्री मोपुदेवी वेंकट रमणा, माननीय मत्स्य पालन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।इस एक्सपो का 5000 से अधिक किसानों ने दौरा किया।

7. आईसीएआर एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा नई दिल्ली में 21 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा आयोजित "विश्व मत्स्यपालन दिवस समारोह" के दौरान आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते मैनेज ने मत्स्यपालन गतिविधियों, एसी व एडीपी एवं एओसी का प्रदर्शन किया।श्री गिरिराज सिंह, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्री, डॉ. संजीव कुमार बालयान, माननीय मत्स्यपालन राज्य मंत्री और श्री प्रताप चंद्र सासिरंगी, माननीय मत्स्यपालन राज्य मंत्री, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए तथा सर्वश्रेष्ठ किसानों एवं उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया।

8. केरल के कोच्चि में 28-30 नवंबर के दौरान आयोजित "एक्वाटिक रिसोर्सेज एंड ब्लू इकोनॉमी (एक्यूएबीई-2019) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में शामिल होकर मैनेज ने सीआईए मत्स्यपालन गतिविधियों और आरकेवीवाई-रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया।

9. कृषि महाविद्यालय, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू), राजेंद्रनगर, हैदराबाद में 11-12 फरवरी, 2020 के दौरान "सजावटी मछली उत्पादन और प्रबंधन" पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैनेज –सीआईए दलनेभाग लिया और मत्स्यपालन गतिविधियों तथा सजावटी मछलियों में उद्यमशीलता के अवसरों की व्यापकता का प्रदर्शन किया।

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (देसी)

इनपुट डीलरों को उपयूक्त कृषि का ज्ञान देकर उन्हें पारा-एक्सटेन्शन प्रोफेशनल के रुप में परिवर्तित करने के लिए, मैनेज ने एक वर्षीय इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा को वर्ष 2003 में प्रारंभ किया, ताकि वे किसानों के क्षेत्रस्तरीय समस्याओं का समाधान कर सके।

कार्यक्रम के उद्देश्यः

- स्थान विशिष्ट फसल उत्पादन टैक्नोलॉजी पर इनपुट डीलरों का ओरिएंटेशन।
- निवेशों के प्रभावी रखरखाव में निवेश डीलरों का क्षमता निर्माण।
- कृषि निवेशों के विनियामक नियमों की जानकारी प्रदान करना ।
- किसानों के लिए गाँव स्तर पर (वन स्टॉप शॉप) कृषि सूचना के लिए निवेश डीलरों को प्रभावी स्रोत के रूप में तैयार करना।

विधि

देसी (DAESI) कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है कि इनपुट डीलर अपने दैनिक व्यापार में अड़चन लाए बिना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। यह कार्यक्रम 48 सप्ताहों में बाँटा गया है, जिसमें 40 कक्षागत सत्र एवं विभिन्न संस्थानों एवं फार्मर फील्ड के लिए 8 क्षेत्रीय दौरों का आयोजन किया जाता है। कक्षागत सत्र और क्षेत्र दौरों को रविवार और स्थानीय बाजार के छुट्टियों के दिन आयोजित किए जाते है। क्षेत्र दौरों का आयोजन स्थान विशेष के कृषि समस्याओं तथा संबंद्ध तकनीकियों से अवगत कराने के लिए आयोजित किए जाते है। उन्हें कीटों की पहचान, तथा पौष्टिकता संबंधी कमियों को पहचानने में प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षण सामग्री स्थानीय भाषा में प्रदान की जाती है और मल्टी मीडिया उपकरणों का कक्षागत विवरण हेतु उपयोग किया जाता है।

मूल्यांकन

प्रत्येक निवेश डीलर का मूल्यांकन द्विमासिक मंच, अर्ध वार्षिकएवं वार्षिक परीक्षा तथा अंतिम प्रयोग परीक्षा जिसमें कौशल प्रदर्शन,नाश कीटों के नमूनों रोग और पौष्टिक कमियों की पहचान, के बाद मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। डिप्लोमा को प्राप्त करने के लिए आवेदक को कम से कम 64 कक्षाओं और कम से कम छः शिक्षण दौरों में उपस्थित रहना होगा ताकि वह अंमित परीक्षा देने योग्य बन सके। डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करने के लिए आावेदक को कम से कम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना होगा।

पाठ्यक्रम शुल्क

पाठ्यक्रम का आयोजन स्ववित्तपोषण (प्रतिभागियों द्वारा 100% कोर्स शुल्क का भुगतान किया गया) के आधार पर रु. 20,000/- शुल्क नामित इनपुट डीलरों से लेकर किया जाता है। इस कार्यक्रम के महत्व को पहचानते हुए

भारत सरकार ने देसी को केन्द्र क्षेत्र की योजना परियोजना (सेन्ट्रल सेक्टार प्लैन स्कीम) के रूप में अक्तूबर, 2015 से बदल दिया जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रत्येक इनपुट डीलर के लिए रू. 10,000/- तक पाठ्यक्रम शुल्क में सब्सिडी दी जा रही है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

दिशा निर्देशों के अनुसार, मैनेज राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी, और राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षा संस्थान (समेती) राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी है। बदले में समेति विभिन्न कृषि प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि कॉलेजों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (आत्मा), डीएटीसी / किसान प्रशिक्षण केंद्रों (एफटीसी) और गैरसरकारी संगठनों आदि के माध्यम से जिलास्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान की गयी प्रगति

वर्ष 2019-20 के दौरान, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, के 332 बैचों में, देसी (डीएईएसआई) कार्यक्रम में कुल 12954 इनपुट डीलरों ने सफलता पूर्वक डिप्लोमा को पूर्ण किया।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में 523 बैचों में कुल 20920 इनपुट डीलर देसी प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसमें से 362 बैचों का निधीयन समर्थन केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से और बाकि 161 बैचों के लिए स्ववित्त पोषण के आधार पर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराख्ंड और पश्चिम बंगाल राज्य कर रहे है।

वर्ष 2019-20 के दौरान देसी के लिए भारत सरकार द्वारा रू.1144.00 लाख की राशी मंजूर की गयी है। इसमें से रू. 795.9 लाख की राशी का उपयोग 18 राज्यों में देसी कार्यक्रम चलाने के लिए उपयोग किया गया है।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों का आयोजन 23-27 सितंबर, 2019 के दौरान केवीके, सुत्तूर, कर्नाटक में सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस इंटरनेशनल (सीएबीआई) के सहयोग से कर्नाटक के देसी फैसिलिटेटरों के लिए सीएबीआई पौध-अनुसार मॉड्यूलों किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान की गयी प्रगति

क्र. सं.	राज्य / एसएएमटीआई	1/4/2019 से 31/3/2020 के दौरान पूरा हुआ		31.3.2020 के दौरान की गयी प्रगति			
		बैचों की संख्या	इनपुट डीलरो की संख्या	बैचों की संख्या			
				सीएसपीएस	स्व-वित्त	कुल	इनपुट डीलरो की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14	546	23	14	14	14
2	बिहार	16	618	51	16	16	16
3	छत्तीसगढ	15	599	10	15	15	15
4	गुजरात	02	77	04	02	02	02
5	हरियाणा	00	00	00	00	00	00
6	हिमाचल प्रदेश	07	274	09	07	07	07
7	जम्मू व कश्मीर	00	00	01	00	00	00
8	झारखंड	18	710	16	18	18	18
9	कर्नाटक (दक्षिण)	40	1567	08	40	40	40
10	कर्नाटक (उत्तर)	30	1177	13	30	30	30
11	केरल	09	340	09	09	09	09
12	मध्य प्रदेश	33	1265	30	33	33	33
13	महाराष्ट्र	41	1629	78	41	41	41
14	ओडीशा	19	743	07	19	19	19
15	पंजाब	02	73	02	02	02	02
16	राजस्थान	12	459	24	12	12	12
17	तमिलनाडु	04	157	04	04	04	04
18	तेलंगाना	11	420	26	11	11	11
19	उत्तर प्रदेश	35	1376	38	35	35	35
20	उत्तराखंड	1	40	01	1	1	1
21	पश्चिम बंगाल	23	884	08	23	23	23
	कुल	**332**	**12954**	**362**	**161**	**523**	**20920**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण [आरकेवीवाई-रफ्तार]

विश्व भर में, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी, सेवा, व्यावसायिक विचार आदि क्षेत्रों में नए उद्यम विकसित करने पर इनक्यूबेटरों का ध्यान आकर्षित की जा रही हैं। भारत सरकार ने पुनरुद्धार करने वाले अपने प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और व्यवसाय विकास पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार करने का भी प्रयास किया है। वर्ष 2019-2020 के दौरान, मैनेज-सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप (सीआईए) ने कुल 54 सामाजिक उद्यमों में से 15 सामाजिक उद्यमों की सहायता की। ये क्षेत्र थे कृषि, कृषि इंजीनियरी, पशु चिकित्सा, खाद्य कृषि वानिकी, स्मार्ट कृषि, मत्स्यपालन और पर्यावरण। कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली आवश्यकताओं और तौर-तरीकों की पूर्ति के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा कृषिव्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करके, नवाचार और कृषिउद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2017-18 में एक नई आरकेवीवाई-राफ्तार स्कीम आरंभ की गई थी।

इसी उद्देश्य हेतु, नावाचार और कृषि-उद्यमिता सेल की संस्थापना की निगरानी के लिए 5 नॉलेज पार्टनर और 24 आर-एबीआई (आरकेवीवाई-एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटरों) का गठन किया गया। आरकेवीवाई–रफ्तार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड नॉलेज पार्टनर के रूप में मैनेज-नवाचार और उद्यमिता केंद्र (सीआईए) को मान्यता दी गई है। मैनेज नॉलेज पार्टनर के रूप में, 1. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल (केएयू), 2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबाद, तेलंगाना (आईआईएमआर), 3. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बतूर, तमिलनाडु, 4. कृषि नवाचार और उद्यमिता सेल, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, (एएनजीआरएयू), तिरुपति, आंध्र प्रदेश के आरकेवीवाई-एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटरों (आर-एबीआई) के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का संचालन और प्रदर्शन करेगा।

आरकेवीवाई–रफ्तार कार्यक्रम

मैनेज कृषि-स्टार्टअप के लिए आरकेवीवाई–रफ्तार के अंतर्गत दो व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनमें एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम (एओपी) और स्टार्टअप एग्री बिजिनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम (एसएआईपी) शामिल हैं।

1. कृषि उद्यमिता ओरिएन्टेशन कार्यक्रम (एओपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों/युवाओं/अनुसंधान करने वाले विद्वानों को उनके नवीन विचारों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य संभावित कृषि उद्यमियों को अन्य स्टार्ट-अप के साथ व्यावहारिक, तकनीकी और व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण व इंटर्नशिप प्रदान करना है; इनक्यूबेटरों के लिए कृषि उद्यमियों की श्रेणी का सृजन और पोषण करना है; जीविका के अन्य उपलब्ध विकल्पों के बीच नवीन विचारों से संबंधित उद्यमशीलता को जीविकाका एक आकर्षक विकल्प बनाना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, चयनित उम्मीदवारों को 5.00 लाख रुपए अनुदान राशि तथा 10,000 रुपये प्रति माह के वजीफे की सहायता के साथ 60 घंटे का कक्षगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और स्टार्ट-अप के लिए स्थान के साथ इंटर्नशिप प्रदान की जाती है।

कृषि उद्यमिता अभिविन्यास कार्यक्रम (एओपी) का पहला जत्था: एओपी का पहला जत्था 27 फरवरी, 2019 को आरंभ हुआ था। कुल 195 प्राप्त आवेदनों में से,इस कार्यक्रम के लिए 19 स्टार्टअप चुने गए और उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण लिया,जिसमें नए विचारों के स्रोत, विचार सत्यापन, स्टार्ट-अप कार्यप्रणाली, आईपी मुद्दों की सुरक्षा, उत्पाद योजना और प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया और व्यापार मॉडल कैनवास आदि शामिल हैं।

कार्यक्रम 26 अप्रैल, 2019 को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद, 19 स्टार्टअप में से 7 स्टार्टअप का चयन किया गया तथा प्रत्येक को 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

कृषि उद्यमिता अभिविन्यास कार्यक्रम (एओपी) का दूसरा जत्था: एओपीका दूसरा जत्था 25 नवंबर 2019 से निर्धारित किया गया था। कुल 332 आवेदनों में से 18 स्टार्ट-अप को अंतिम मूल्यांकन के लिए चुना गया था। सात अलग-अलग राज्यों से चयनित किए गए प्रतिभागियों को 15 नवंबर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तक मैनेज, हैदराबाद में आरकेवीवाई-रफ्तार के अंतर्गत कृषि उद्यमिता अभिविन्यास कार्यक्रम जत्था II में प्रशिक्षित किया गया था।

एक दो दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद 15 दिनों के फील्ड कार्य की जानकारी दी गई थी। इस वेबिनार में प्रतिभागियों ने अपने विचारों की व्यवहार्यता, बाजार सर्वेक्षण आदि पर कार्य किया। कैंपस में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने अपने विचारों को परिष्कृत किया, डिजाइन थिंकिंग,बाजार अवसरों तथा अपने उत्पादों/सेवा के लिए रणनीति बनाना वित्तीय लेखा-जोखा और नकदी प्रवाह प्रक्षेपण का निर्माण करना सीखा एवं हैदराबाद के विभिन्न इंक्यूबेटर केंद्रों जैसे टी-हब और इक्रिसेट-एआईपी की खोज की।

प्रशिक्षण के दूसरे चरण में प्रतिभागियों कोविभिन्न कंपनियों और संस्थानों जैसे एएलसी इंडिया लिमिटेड, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (भाचाअनुसं), केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रिडा), आनंद फार्म, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस) बेंगलूरू, जीकेवीके आदि से इंटर्नशिप कराया गया था। इंटर्नशिप पूरा करने के बाद, संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागियों को पिच डेक तैयार करना सिखाया गया। 10 जनवरी, 2020 को प्रतिभागियों ने अपनी सेल्स पिच सीआईसी समिति के समक्ष रखी।

2. स्टार्ट-अप एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेशन प्रोग्राम (एसएआईपी)

यह कार्यक्रम उद्यमों को बढ़ावा देते हुए उनके नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का दोहन करके रोजगार सृजन और धन अर्जन की दिशा में कार्य करने वाले कृषि स्टार्ट-अप की सहायता करता है। उद्देश्य हैं- आर-एबीआई के भीतर योग्य इनक्यूबिटी के लिए बीज की सहायता सुनिश्चित करना; न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) को विपणन योग्य बनाना तथा उत्पाद और व्यवसाय मे वृद्धि करना; वृद्धि के लिए नवीन समाधानों /प्रक्रियाओं/ उत्पादों/ सेवाओं / व्यापार मॉडलों आदि के आधार पर उनके दृष्टिकोण या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) में तेजी से प्रयोगकार्य और संशोधन के लिए प्लैटफार्म प्रदान करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, चयनित उम्मीदवारों को 25.00 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता के साथ 8 सप्ताह की आवासीय प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और निवेश की सुविधा सहित दो वर्ष का इंक्युबेशन सहायता भी प्रदान किया जाता है।

स्टार्टअप एग्री-बिज़नेस इन्क्यूबेशन प्रोग्राम (एसएआईपी) का पहला जत्था:

स्टार्टअप एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम (एसएआईपी) का पहला जत्था 22 फरवरी, 2019 को आरंभ हुआ था। कुल 131 आवेदनों में से 17 को चयनित किया गया था। चयनित स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण का पहला चरण मार्च के पहले सप्ताह तक और दूसरा चरण अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक संपन्न हो गया था। स्टार्टअप ने विभिन्न पहलुओं जैसे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और इन्क्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र, स्टार्ट-अप उद्यमों के प्रकार, बाजार योजना और लिंकेज, पूंजी के स्रोत और फंडिंग के प्रकार, प्रबंधन में विकास की रणनीति और नवाचार के जीवन चक्र आदि पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर 11 स्टार्टअप को अनुदान सहायता के लिए चयनित किया गया।

स्टार्टअप एग्री-बिज़नेस इन्क्यूबेशन प्रोग्राम (एसएआईपी) का दूसरा जत्था:

स्टार्टअप एग्री-बिजनेस प्रोग्राम का दूसरा जत्था जून 2019 माह में आरंभ किया गया था। कुल 223 आवेदनों में से विभिन्न राज्यों से 21 स्टार्टअपों ने नवीन विचारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर था जैसे विपणन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, व्यवसाय योजना की तैयारी, और पिचिंग। प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ।

मैनेज - नवाचार और कृषि विकास केंद्र (सीआईए)

- मैनेज - सीआईए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आरंभिक अवस्था में कृषि स्टार्टअप की सुविधा के लिए नियमित इन्क्यूबेशन कार्यक्रम चलाता है। मैनेज - सीआईए को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। ये व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए द्वैण्ड घोलिंग सहायता प्रदान करता है और सदस्यता कार्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करता है।
- कृषि विकास -एक त्वरक कार्यक्रम के माध्यम से, मैनेज - सीआईए आधारभूत जमीनी स्तर पर नवाचारों की पहचान करता है, प्रति वर्ष 100 चयनित स्टार्ट-अप के लिए निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों के नेटवर्क को निधि, संरक्षक और कार्यालय के लिए स्थान की सुविधा प्रदान करता है। अब तक 8 राज्यों से 150 उद्यमियों का चयन किया गया है।
- मैनेज - सीआईए के इंपल्स कार्यक्रम की परिकल्पना कृषि- संरक्षक सेवाओं को मजबूती प्रदान करते हुए कृषि-उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है। यह इच्छुक उद्यमियोंको संरक्षकों के साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसाय संस्थापित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण आवश्यकता की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 200 मेन्टीस वालों और 25 मेन्टरों ने नामांकन किया है।
- मैनेज-नवाचार और कृषि विकास केंद्र (सीआईए) को आरकेवीवाई-रफ्तार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड नॉलेज पार्टनर के रूप में मान्यता दी गई है।
- कुल मिलाकर, मैनेज इनक्यूबेशन गतिविधियों में 51 स्टार्ट-अप, 700 सदस्य, 27 संरक्षक शामिल हैं और आरकेवीवाई-रफ्तार परियोजना के अंतर्गत 83 स्टार्ट-अप / उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

मैनेज - सीआईए द्वारा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना

मैनेज - सीआईए ने कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन और आरकेवीवाई-रफ्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को उन्मुख करने और प्रदर्शन करने के लिए स्टाल स्थापित करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लिया:

- पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और एक्सपो: स्टार्ट एंड स्टैंड अप नॉर्थ ईस्ट,एक 3-दिवसीय शिखर सम्मेलन और व्यापार मेले का आयोजन एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एमएसएमई मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा समर्थित) तथा भारतीय कार्बनिक उद्योग परिसंघ (सीओआईआई) द्वारा 17 से 19 जनवरी 2020 के दौरान गुवाहाटी में किया गया।
- पीजेटीएसएयू, हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यशाला और एक्सपो
- 21 से 23 दिसंबर, 2019 तक आईसीएआर-एनएएआरएम, हैदराबाद, तेलंगाना में एस एंड टी आधारित उद्यमिता विकास प्रदर्शनी पर एनएएसआई और परिसंवाद का 89 वां वार्षिक सत्र।
- मैनेज में 21 दिसंबर, 2019 को "युवा उद्यमिता के लिए अवसरों को बढ़ावा देने" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि-स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई)

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी (एनएमएईटी) पर राष्ट्रीय मिशन के उप-मिशन कृषि विस्तार (एसएमएई) के अंतर्गत लागू किया गया एक घटक है। वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ की गई एसटीआरवाई स्कीम का उद्देश्य कृषि आधारित व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने इस स्कीम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) को सौंपा है। राज्यों में इस स्कीम को राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों (समेति) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

एसटीआरवाई के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों की अवधि सात दिनों की है जिसमें एक दिन की यात्रा शामिल है और इसमें 15 प्रतिभागियों का बैच है। ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), किसान प्रशिक्षण केंद्रों (एफटीसी), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (एटीएमए), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) या समेति(एसएएमईटीआई) द्वारा राज्य / जिला स्तर पर चिन्हित किए गए किसी भी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। 15 प्रतिभागियों के बैच के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का बजट 42,000/- रु.(15रु. X 7 दिन x 400 रु.) है.

क्र.सं.	राज्य	आवंटित कार्यक्रमों की संख्या	राशि जारी की गई (रुपये लाखों में)
1	असम	40	16.80
2	मणिपुर	43	18.06
3	मेघालय	45	18.90
4	मिजोरम	33	13.86
5	नगालैंड	39	16.38
6	सिक्किम	10	04.20
7	त्रिपुरा	40	16.80
8	आंध्र प्रदेश	40	16.80
9	छत्तीसगढ़	25	10.50
10	गुजरात	20	08.40
11	झारखंड	25	10.50
12	कर्नाटक (दक्षिण)	15	06.30
13	कर्नाटक (उत्तर)	15	06.30
14	केरल	10	04.20
15	महाराष्ट्र	60	25.20
16	ओडीशा	20	08.40
17	पंजाब	25	09.91
18	तमिलनाडु	40	16.80
19	तेलंगाना	35	14.70
20	उत्तराखंड	10	04.20
21	पश्चिम बंगाल	20	08.40
	कुल:	**610**	**255.61**

फर्टिलाइजर डीलर्स के लिए एकीकृत पोषण प्रबंधन (सीसीआईएनएम) पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

पृष्ठभूमि

कृषि में उर्वरक एक महत्वपूर्ण कृषि इनपुट है, जिसका ज्यादातर विपणन डीलरों द्वारा किया जाता है। अधिकांश किसान उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित जानकारी के लिए उर्वरक डीलरों पर निर्भर हैं। इसके मद्देनजर, वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) उर्वरक डीलरों के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (सीसीआईएनएम) पर 15 दिनों का एक आवासीय सर्टिफिकेट कोर्स कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन और परामर्श सेवाओं पर पेशेवर रूप से सक्षम बनाना है। सर्टिफिकेट कोर्स से उम्मीद है कि इन प्रशिक्षित उम्मीदवारों का पैरा विस्तार पेशेवरों के रूप में उपयोग से सार्वजनिक और निजी विस्तार प्रणालियों को मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- उर्वरक/भावी डीलरों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करना
- उर्वरकों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर उर्वरक / पैरा विस्तार पेशेवरों के रूप में भावी डीलरों का विकास करना

कार्यविधि

यह कार्यक्रम उर्वरक/भावी डीलरों के लिए आवासीय कार्यक्रम के रूप में 15 दिनों की अवधि के लिए निरंतर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक बैच में कुल 30 उम्मीदवार होते हैं। इस कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान स्टेशन, फ्रीलांसरों तथा विषय के अन्य विशेषज्ञों के रिशोर्स व्यक्तियों द्वारा क्लास रूम सत्र और अनुभवी ज्ञान दोनों शामिल हैं तथा निकट के कृषि फार्मों / कृषि विश्वविद्यालय के आईएनएम भूखंडों / अनुसंधान संगठनों / केवीके / अभिनव किसान क्षेत्रआदि के एक्सपोजर विजिट शामिल हैं।क्षेत्र का दौरा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में हाल की प्रगति पर जानकारी प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए है।

मूल्यांकन

उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन मध्यावधि परीक्षा, अंतिम परीक्षा, असाइनमेंट और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है।

पाठ्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम स्व-वित्त पोषण के आधार पर आयोजित किया जाता है। 30 उम्मीदवारों के बैच के लिए 15 दिनों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क 2500.00 रुपए प्रति उम्मीदवार है।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

दिशानिर्देशों के अनुसार, मैनेज राष्ट्रीय स्तर का कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि समेति (एसएएमईटीआई) राज्य स्तर का नोडल एजेंसी है। एसएएमईटीआई विभिन्न कृषि प्रशिक्षण संस्थानों जैसे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि महाविद्यालयों, केवीके, आत्मा(एटीएमए), डीएटीसी/ एफटीसी तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान हुई प्रगति

वर्ष 2019-20 के दौरान, 57 बैचों में कुल 1710 उर्वरक डीलरों ने बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में सीसीआईएनएम कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्तमान में, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में 67 बैचों में कुल 2010 उर्वरक डीलरों/ उम्मीदवारों का सीसीआईएनएम कार्यक्रम जारी है।

सारणी 1. दि.31.03.2020 तक सीसीआईएनएम कार्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का विवरण.

क्र.सं.	राज्य का नाम	बैचों की संख्या (31.03.2020 को पूरी हुई)	उम्मीदवारों की संख्या (31.03.2020 को पूरी हुई)
1.	बिहार	12	360
2.	हरियाणा	06	180
3.	कर्नाटक	03	901
4.	उत्तरप्रदेश	36	080
कुल		**57**	**1710**

5. शिक्षा कार्यक्रम

स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध)

[पीजीडीएम (एबीएम)]

वर्ष 1991 में हुए आर्थिक सुधार ने आर्थिक व्यवस्था में रूपरेखा संबंधी मुख्य परिवर्तन लाए है जिसने भारतीय कृषि की ढ़ाँचे को परिवर्तित कर दिया। इससे देश के कृषि व्यापार क्षेत्र में कई असामान्य अवसर खोला है।

इसके साथ ही अन्य समवर्ती शक्तियों ने एग्रि बीजिनेस के क्षेत्र में प्रबंधकीय कौशलों की माँग को तीव्रतर किए है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज ने दो वर्षीय पूर्ण कालिक, आवासीय स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध) को वर्ष 1996 में स्व-वित्तीयन आधार पर प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मान्यता प्राप्त हुई है और नेशनल बोर्ड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीस ने मैनेज के पीजीडीएम (एबीएम) को किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय का एमबीए के साथ समरूपता प्रदान की है।

उद्देश्य

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि, खाद्यान्न, कृषि बैंकिंग तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में केरियर के लिए कृषि व्यापार नेताओं एवं टेक्नो-प्रबंधकों को तैयार करना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- एग्री-व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विषय का विकास करना ताकि युवा व्यवसायिकों को सक्षम प्रबंधकों के रुप में तैयार कर सकें।
- एग्रि बिजिनेस क्षेत्र में प्रबंधकीय निर्णायन हेतु एग्री-व्यापार क्षेत्रों का पर्याप्त जानकारी, कौशल तथा उचित व्यवहार प्रदान करना ।
- कृषि में बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रभावी उद्यमकर्ता के रुप में तैयार करना।

प्रवेश प्रक्रिया

मैनेज ने आवेदकों के चयन करने हेतु कैट (सीएटी) स्कोर, सामूहिक विचार-विमर्श, प्रपत्र लेखन, एक्सटेम्पोर / माइक्रो प्रजन्टेशन, कार्यानुभव, अकादमिक अभिलेखों तथा वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर उद्देश्य आधारित मापदण्ड को अपनाया है।

कार्यक्रम डिजाईन

पी जी डी एम (ए बी एम) कार्यक्रम केस आधारित अभिगम, व्याख्यान, सिमुलेशन गेम, उद्योग से प्रायोजित ग्रीष्म एवं लाईव परियोजनाओं से युक्त होता है ताकि छात्र कृषि एवं अन्य व्यापारिक परिवेश में प्रबंध को आत्मसात कर उनका अनुपालन करें। कृषि व्यापार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप इस कार्यक्रम की रुपरेखा को तैयार किया गया है जिसे 116 क्रेडिटों के साथ VII तिमाहियों में बाँटा गया है। पी जी डी एम (ए बी एम) के

पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई और इसे अद्यतन रखने और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप एक विशेष ज़पैन लद्वारा संशोधित किया गया। इस कार्यक्रम के 43 विषयों (116 क्रेडिट) को व्यापक रुप से आधारभूत, फ़ंक्शनल, सेक्टोरल तथा सामान्य पाठ्यक्रमों के रुप में बाँटा गया है। इस पाठ्यक्रम में एग्रि-इनपुट मार्केटिंग, कृषि निर्यात, प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रोक्यूरमेंट प्रबंधन, सप्लाई-चेन मैनेजमेंट, बॉन्ड व कृषि उत्पाद प्रबन्धन; ग्रामीण विज्ञापन स्वास्थ्य और संचार, कमॉडिटी फ्यूचर्स, ट्रेडिंग और ऑप्शन्स, भागीदारी विस्तार प्रबंधन, ऑपरेशन्स रीसर्च, क्वान्टिटेटिव टेकनीक्स फर एग्रिबिजिनेस, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक व्यवहार इतयादि

गाँव का दौरा

ग्रामीण जनता के साथ 15 दिनों का समय व्यतीत करने से, विद्यार्थियों को, किसानों की समस्याओं तथा कृषि क्षेत्र में विकास की ससंभावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। इस अध्ययन दौरे के अंत में, संवृद्धि के विकास एवं अवसरों के बीच आनेवाली अड़चनों का आकलन व पहचान करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

सम्मर इंटर्नशिप

छात्रों को प्रायोगिक क्षेत्र स्तरीय अनुभव प्रदान करने हेतु चौथी तिमाही सम्मर इंटर्नशिप के लिए रखा गया है। जिसके दौरान छात्र कृषि व्यापार-कंपनियों द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना तथा उन्हें क्षेत्रगत प्रबंधकीय कौशलों में दक्ष बनाना है। परिस्थितियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराकर ग्रीष्म परियोजनाओं जिसके 10 क्रेडिट हैं और सौ अंकों के लिए होता है, का मूल्यांकन इंटर्नशिप प्रदान करने वाली कंपनी के निरीक्षक या किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है। 2018-20 बैच के सभी छात्र सम्मर इंटर्नशिप के लिए चुने गए है।

छात्रों को अपने यहाँ इंटर्नशिप प्रस्तावित करने वाली कंपनियाँ हैं: "एडेमा, एएससीआई, बीएएसएफ, बेयर क्रॉप साइंस, कारगिल इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, कोर्टेव एग्रीसाइंस, क्रिसिल लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड,

एफएमसी, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, ग्रोइंडिगो, आईसीआरआईएसएटी, आईटीसी-एबीडी, आईटीसी-एफबीडी, महिको, नेडस्पाइस, पीडब्ल्यूसी, इंडिया, सैम एग्रीटेक, समुनती, यूपीएललिमिटेड, टेक्नोसर्व"। इसके अलावा छात्र अन्य अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं को भी लेते है।

औद्योगिक दौराः

पाँचवी तिमाही के दौरान छात्र इम्डस्ट्रियल विजिट करते हैं, जिसका उद्देश्य एग्रि बिजिनेस कंपनियों से जुड़ना और उन्हें पीजीडीएम (एबीएम) के गुण और शक्तियों के बारे में जानकारी देना है। वे इन कंपनियों में अन्तिम प्लेसमेंट और सम्मर इंटर्नशिप की संभावनाओं को भी देखते है। पीजीडीएम (एबीएम) के 2018-20 बैच ने 150 कंपनियों का दौरा किया वरिष्ठ कार्यकारियों के समक्ष प्रजेन्टेशन दिए।

स्पाइस

इस त्रैमासिक पत्रिका पी जी डी एम (ए बी एम) के छात्रों द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में इंडस्ट्री इंटरफेस कार्यक्रम, गेस्ट लेक्चर्स, अनेक कार्यक्रम, छात्रों के प्रपत्र तथा संकाय पुनर्निवेशन सहित नवीन कैंपस समाचार प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष के दौरान चार अंक प्रकाशित हुए है।

अंतिम स्थापनाः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2018-20 बैचके सभी छात्रों को नियुक्ति प्रदान की 29 कंपनियों ने मैनेज का दौरा किया। औसतन सीटीसी रु. 10.05 लाख प्रति वर्ष के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी जिसमें राशि रु. 5.50-18.50 लाख प्रति वर्ष के दर से रहा है ।

छात्रों को नियुक्त किये कंपनियाँ हैं -"एग्रीवॉच, बीएएसएफ,बीएएसएफ, बेसिक्स सब-के इटरैनसेक्शन लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, क्रिसिल, ग्रीन एग्रीवोल्यूशन प्रा. लि. (देहात), धनलक्ष्मी सीड्स, फेडरल बैंक, गोदरेज एग्रोवेट, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, आईटीसी (एबीडी), जापफा कॉम्फेड, जेके एग्रोटिक्स लिमिटेड, केमिन इंडस्ट्रीज, महिको सीड्स, मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज लि., मोर्डोर इंटेलिजेंस, नामधारी सीड्स प्रा. लिमिटेड, निनजाकार्ट, पीडब्ल्यूसी इंडिया, समुनती, सल्फर मिल्स लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, यस बैंक"।

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

छात्रों के बीच समस्या निवारण कौशल को विकसित करने के लिए, अक्टूबर के महीने में शीतकालीन परियोजनाओं को लेने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। शीत कालीन इंटर्नशिप परियोजनाओं के तहत, छात्र कॉर्पोरेट के लिए समस्या केंद्रित विषय ले रहे हैं।

अक्टूबर, 2018 के महीने में, पीजीडीएम (एबीएम) 2018-19 बैच ने विभिन्न कृषि व्यवसाय कंपनियों के साथ एक महीने की लाइव परियोजनाएं की हैं।

कार्यक्रम प्रबंधः

शैक्षणिक समिति, परीक्षा समिति और अपील समिति द्वारा कार्यक्रम का दिशानिर्देशन किया जाता है।

पीजीडीएम (एबीएम) श्रेणीकरण

कार्यक्रम को दी गयी श्रेणी निम्न रुप से है बिजिनेस टुडे रैंक 2019

- भारत में 40वाँ उत्तम कॉलेज
- सीखने के अनुभव में 12 वाँ स्थान
- लिविंग एक्सपीरियंस में 22 वाँ स्थान

'सामान्य अतिथि व्याख्यानों' के माध्यन से बिजिनेस लीडरों के साथ परिचर्चाः

औद्योगिक इंटरफेस के एक भाग के रूप में, उद्योग व शिक्षा जगत के कुछ प्रविष्ठित व्यक्तियों को, विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करने तथा व्यक्तिगत अनुभवों को बाँटने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान विभिन्न विषयों जैसे-वित्त, विपणन, प्रचालन तथा प्रापण आदि पर अधिकारियों द्वारा प्राकश डाला जताा है। सरकारी संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ एवं व्यावसायिक अधिकारियों को नीतिगत संरचनाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कृषि की संवृद्धि और विकास में आने वाली उलझनों आदि पर चर्चा करने हेतु बुलवाया जाता है। इसके फलस्वरूप, इस उद्योग की श्रेष्ठ न्यूनतम पद्घतियों व आने वाली चुनौतियेां से विद्यार्थी का अवगत होते हैं। साथ ही, विद्यार्थियों में न केवल व्यापारिक सक्षमताओं का विकास होता है, बल्कि विकास के प्रति उनका नजरिया भी विकसित होता है। इस वर्ष, विद्यार्थियों के साथ चर्चा में शामिल कुछ अधिकारी निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	नाम	संगठन
1.	मोरडोर इंटेलिजेंस	श्री अविनाश देशमनागलम, अनुसंधान प्रबंधक - कृषि और खाद्य एवं पेय
2.	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री उन्नीकृष्णन विजयन, वरिष्ठ प्रबंधक, खरीद
3.	गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड	श्री अनिलगुप्ता, विपणन प्रमुख श्री रितेश देशमुख, डी जी एम -फसल संरक्षण व्यवसाय
4.	सुमितोमोकेमिकल्स इंडिया लिमिटेड	श्री सुधीर कुमार, मार्केटिंगलीड- हर्बिसाइड्स
5.	रत्नदीप सुपरमार्केट प्रा.लि.	श्री के वी एस नरसिम्हाराव, प्रमुख एफएंडवी
6.	लिमग्रेन इंडिया	श्री सतीश जी एस, प्रबंध निदेशक
7.	नेस्ले इंडिया लि.	श्री मुकेश कुमार, एचओडी प्रोक्योरमेंट (कमोडिटीज एंड कंटेंट्स), श्री आशीष भटनागर, प्रबंधक (खरीद)
8.	निनजाकार्ट (63 आईडेस इन्फोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड)	श्री एंटोक्लिंटन, एसोसिएट डायरेक्टर
9.	डिजिटलग्रीन	श्री प्रीतम कुमारनंदा, क्षेत्रीय प्रबंधक सु श्री अर्चना, उपप्रमुख- एपीएंडटीएस
10.	जपफा कॉमफी इंडिया प्र.लि.	श्री हेमंतवागरे, एजीएमएचआर
11.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	श्री जे.वी. नरसिम्हम, पूर्व उपाध्यक्ष
12.	डीएस ग्रुप	सु श्री सिमिन अस्करी, उपाध्यक्ष- कॉर्पोरेट मानव संसाधन
13.	ईस्टवेस्टसीड्स	श्री चंद्रमूर्तिटी., वाणिज्यिक निदेशक
14.	पीडब्ल्यूसी इंडिया	श्री रवींद्रग्रोवर, एसोसिएट डायरेक्टर श्री अंकुरबनर्जी, सिनियर एसोसिएट - कैम्पसरिलेशंस और ब्रांडिंग-टैलन्ट ऐक्विज़िशन
15.	बी ए एस एफ	श्री ब्रह्मानंद मल्लिक, प्रमुख - व्यवसाय योजना, फसल सुरक्षा प्रभाग

16.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	श्री शंकरसुब्रमण्यन, अध्यक्ष (उर्वरक) श्री कालिदास पी, कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्केटिंग (फर्टएंडऑर्गफर्ट) श्री माधब अधिकारी, एवीपी - बिक्री और विपणन (एसएनडी) श्री सब्यसाचीरे, सीनियरजीएम - एचआर (सीपीसीबीयू) श्री प्रभुस्वामी के, सीनियरएवीपीएंडहेड - फॉर्मुलेशन - सेल्स एंड मार्केटिंग (सीपीसी)
17.	एबी इन बेव	श्री अखिल श्रीवास्तव, निदेशक दक्षिण एशिया
18.	समुनती ग्रूप	श्री गणेशजीसी, सीनियर वीपी, बिजनेस श्री राममोहन, वीपी, बिजनेस
19.	यू पी एल लि.	श्री बीवीएस सतीश, एसबीयूलीड, यूपीएल
20.	कोर्टेवा एग्रीसिस	श्री बीबिनफिलिप, टैलन्ट ऐक्विज़िशनलीडर श्री संजीव गुलाटी, फील्डफोर्स इफ़ेक्ट प्रबंधक (बीज और फसलसंरक्षण) दक्षिण एशिया
21.	सी आर आई एस आई एल	श्री पुषन शर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर
22.	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी भारत	श्री गुरुप्रसाद वी आर, राज्यव्यापार प्रमुख- कर्नाटक श्री वेणुगोपाल राजू, राज्यव्यापार प्रमुख- एपी श्री अमृतवेल सी, जोनल- एचआरबीपी
23.	कारगिल एनिमल नूट्रिशन इंडिया	श्री कौशिक सिन्हा, निदेशक - रणनीतिक विपणन और प्रौद्योगिकी
24.	महयकोग्रो	डॉ.चंद्रकुमार सारागुर, बिजनेस यूनिटहेड श्री शंकरन लवाडे, नेशनल मार्केटिंग मैनेजर
25.	एफएमसी	श्री बकुल जोशी, मार्केटिंग हेड- इंडिया
26.	बेसिक्ससब-के	श्री चंद्रशेखरपी., डीवीपी-पीपलमैनेजमेंट श्री गौरी देवी, एवीपी- संचालन श्री नम्रता सहगल, एवीपी- मार्केटिंग और एसपीएम
27.	सुलफुलमिल्स लि.	सु श्री लविता थेरोथ, डीजीएम - एचआर एंड एडमिन श्री जयरामि रेड्डी, वीपी - बिक्री और विपणन
28.	केपीएमजी	श्री निर्वाण भट्टाचार्य, एसोसिएट निदेशक श्री इफ्तेखार खान, प्रबंधक
29.	बिलट लि.	श्री मुकेशसी मधुकर, वीपी - खरीद
30.	सिंजेन्टा	श्री जॉयदीप दास, उत्पाद प्रबंधक - कॉर्नसीड्स
31.	हर्बालाइफ	श्री शशिशेखर, निदेशक - ग्लोबल स्ट्रेटेजिकसोर्सिंग
32.	बायर क्रॉपसा इंसलि.	श्री अरिंदम मुखर्जी, परियोजना प्रबंधक, फसलदक्षता ए पी ए सी
33.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	श्री विशाल जैन, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक
34.	प्रीमियर इरीगेशन एडिटेकप्रा.लिमिटेड -इडिया	श्री जे वी रत्नम, उपाध्यक्ष
35.	एडीएम इंडिया	श्री पल्लव विभु, सहायक प्रबंधक ब्रांडेड तेल

गौरवान्वित क्षण

आईआईएम- अहमदाबाद, आईआईएम- रांची, आई एसबी - हैदराबाद, आईआईएम- त्रिची,आईआईएम-मद्रास,आई आई टी - हैदराबाद, आईएम टी -गाजियाबाद,आई एम टी - हैदराबाद,नार्म - हैदराबाद, सी सी एस एन आई ए एम - जयपुर, एन एम आई एम एस - बैंगलोर,एस आई बी एम -हैदराबाद,एन टी पी सी आदि प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों और संगठनों में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रोंने भागलिया और पुरस्कार प्राप्त किया।

आयोजन

मैनेज प्रबंधन पीजीडीएम (एबीएम) ने निम्न लिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया:

- दि बी-फेस्ट "कृषि चाणक्य" का आयोजन 16 और 17 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया जिसमें कार्यक्रम जैसे 'आकांक्षा' (एक बी -प्लैन प्रतियोगिता), 'खोज' (एक सामाजिक विचार), 'सुशोध' (एक केस स्टडी प्रतियोगिता), 'विश्लेषण' (एक वित्तीय नमूना), 'शिखर' (एक कृषि सम्मेलन), 'धुरिब' (उत्तम प्रबंधक), अर्थाचार्य (एक व्यापार विचार) और एक मानव संसाधन कार्यशाला था। इस वर्ष कृषि चाणक्य कार्यक्रम डैटा एनलिटिक्स के आधार पर रहा जिसका नाम 'दत्तांश' नामी संस्थाओं जैसे आई आई एम, आई और अन्य बी स्कूलों के छात्र बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लिया।
- उन्नयन स्नातक के छात्रों के लिए जनवरी 2020 में आयोजित एक ऑनलाईन कार्यक्रम है जिसमें क्विजार्ड (प्रश्नोत्तरी), बुल्स एण्ड बेर्स्व (सिमुलेशन) ग्लिम्प्स (फोटोग्राफी), पापराजी (वीडियोग्राफी), एग्रिग्राफी (लेखन), इन्सेप्ट (स्टार्ट अप आइडिया) और एस्पैनसॉन (विपणना प्रतियोगिता)
- दि लिटररी फेस्ट - 'लिट-ओ-मिलेन्ज' का आयोजन 22-24 फरवरी, 2020 को किया गया। कुल 12 कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें है वाद-विवाद, कॉलेज, आशुभाषण, कविता लेखन, लघु कथाएं और आलेख लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और बिजिनेस तम्बोला और कुछ ऑनलाईन कार्यक्रम रहा।
- अंतर महाविद्यालय स्पोर्टस मीट "ओलम्पस - 2020" का आयोजन 1 से 3 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित किया गया। मैनेज छात्रों के अलावा, आई बी एस, टी आई एस एस, एस आई बी एम, पी जे एस टी ए यू, आई आई पी एम और देश के 9 अन्य कॉलेजों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- जेनित - 2020 - स्पोर्टस मीट का आयोजन 21 और 22 जनवरी, 2020 को किया गया। छात्रों ने सभी मुख्य खेलों में यथा शटिल बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्क्वेश, वॉलीबाल, टेबुल टेनिस, स्नूकर और आठ अन्य खेल।
- पूर्व छात्रों का मिलन - मैनेज में लगभग 900 सदस्यों के साथ पूर्व छात्रों का नेटवर्क है उनमें से कई लोग कृषि व्यापार के क्षेत्र में वरिष्ठ पदों में कार्य कर रहे है। पी जी डी एम (ए बी एम) किा वार्षिक अल्यूमिनी मीट 18 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया।
- दीक्षांत समारोह: पी जी डी एम (ए बी एम) का 5 वां दीक्षांत समारोह 18 अगस्त, 2019 को पी जी डी एम (ए बी एम) के बैच 2017-19 के लिए आयोजित किया गया। श्री एल.वी. सुब्रमणियम, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।

अन्य गतिविधियां

स्टॉक इन्वस्टमेंट स्कीम

शेयर बाजार की कार्य पद्धति से छात्रों को परिचित कराने और निवेशकी आदत को बढ़ावा देने हेतु, छात्रों के लिए' स्टॉक शेयर में निवेश योजना' की शरुआत वर्ष 2015 से की गयी। इस योजना के अंतर्गत, प्रति छात्र 2000/- रु. की राशि शेयर बाजार में निवेश के लिए छात्र की जमानती जमा से छात्र की टीमों को हस्तांतरित की जाती है। उन्हे मॉक शेयर ट्रेडिंग और निवेश करने वाले प्रतिष्ठित बैंकरों द्वारा अतिथि व्याख्यान के माध्यम से स्टॉक मार्केट के उतार-चढ़ाव से भी अवगत कराया जाता है।

आपकी स्वयं की पुस्तक योजना

इस योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष 5000/- रु. की राशिट् यूशन शुल्क के साथ प्रत्ये कछात्र से लिया जाता है तथा प्रासंगिक विषय विशिष्ट किता बेंखरी दी जाती हैं और छात्रों को स्थायी रूप से दे दी जाती हैं। यह योजना वरिष्ठ और जूनियर बैच केछात्रों के लिए कार्या न्वित किया जारहा है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

शैक्षणिक वर्ष 2014 से सभी छात्रों के लिए 'स्वास्थ्य बीमा योजना 'शुरू की गई, जिस में अस्पता लमें भर्ती के दौरान रोग के उपचार लागत को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों काबीमा किया जाता है।

मैनेज - योग्यता - सह - साधन छात्र वृत्ति

मैनेज जद्वारा उन छात्रों को छात्र वृत्ति दी जाती है, जिनकी आय प्रति वर्ष 6 लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा जो शिक्षण में उत्कृष्ट भी हैं. वर्षमें 20 छात्र वृत्तियाँ दी जाती हैं ओर प्रत्येक कामूल्य 1 लाख रु. है।

शैक्षणिक मेरिट छात्र वृत्ति

पाठ्य क्रम में अव्वल, उपस्थिति में अव्वल, प्रथम वर्ष और द्वितिय वर्ष के विषय में अव्वलक्षात्रों को वार्षिक शैक्षणिक मेरिट (उत्कृष्टता) छात्रवृत्ति दी जाती है. छात्रवृत्ति का मूल्य 7,500/- रु. से ले कर 15,000/- रु. तक है।

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

विस्तारित अधिदेश के साथ मजबूती जीवंत और उत्तरदायी विस्तार वितरण तंत्र कृषि में तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यकता है। कृषि विस्तार को विषय वस्तु, दृष्टिकोण, संरचना, प्रक्रियाओं और उनके वितरण और कार्यान्वयन के संदर्भ में नई चुनौतियों और सुधारों की आवश्यकता है। भारत में लगभग एक लाख सरकारी विस्तार अधिकारी हैं। ये विस्तार अधिकारी किसानों की बड़ी आबादी को विस्तार सहायता प्रदान करने की एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। वे भारतीय कृषि में गंभीर चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसे कि छोटे किसानों के बहुमत, विशाल उपज अंतराल, आदानों के उपयोग में असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट। सरकारी विस्तार प्रणाली अपरिहार्य है और भारतीय कृषि की गति और विविधता से मेल खाने के लिए इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, एग्रीबिजनेस कंपनियों, किसान संगठनों, एग्रीप्रेन्योर, इनपुट डीलर्स, एनजीओ और सहकारी संगठनोंकी बड़ी संख्या में निजी विस्तार व्यवस्थाएं हैं, जो निचले स्तर पर सरकारी विस्तार प्रणाली के साथ साझेदारी के पूरक, काम कर रहे हैं। विस्तार वितरण प्रणाली में उनकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

सरकारी और निजी विस्तार प्रणाली के सर्वोपरि महत्व को महसूस करते हुए, मैनेज ने केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 2007 में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट (PGDAEM) शुरू किया था।। "राज्यों को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को सामान्य राज्यों, पूर्वोत्तर और तीन हिमालयी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए क्रमश: 60%, 90% और 100% की सहायता मिलती है। शेष प्रतिशत हिस्सा, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। पी जी डी एई एम का उद्देश्य भागीदारी निर्णय लेने के लिए नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के साथ विस्तार अधिकारियों को सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें कृषि विस्तार में विभिन्न विस्तार मॉडल और विकास के बारे में जानकारी मिलती है और उनके तकनीकी-प्रबंधकीय दक्षताओं को बढ़ाता है।

पाठ्यक्रम संरचना और सामग्री

कार्यक्रम में 30 क्रेडिट हैं और दो सेमेस्टर में बाँटा गया हैं। एक क्रेडिट 30 घंटों के अध्ययन के बराबर है। पहले सेमेस्टर में प्रत्येक कोर्सके एकएसाइनमेंट के साथ पांच एसाइनमेंट होते हैं, और दूसरे सेमिस्टर में एक कोर्स का एसाइनमेंट के साथ चार कोर्स और एक प्रोजेक्ट वर्कहोता है। कार्यक्रम मुद्रित पठन सामग्री, ई-लर्निंग संसाधनों (प्री-रिकॉर्डेड डीवीडी मॉड्यूल) और व्याख्यान श्रृंखला-सह-संपर्क कक्षाओं के साथ समर्थित है। परीक्षाओं के शुरू होने से पहले व्याख्यान श्रृंखला-सह-संपर्क कक्षाएं राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों (एसएएमईटीआई) या संबंधित राज्य के किसी भी पहचानी गई संस्थान में प्रत्येक सेमेस्टर में पांच दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सत्र-i व ii हेतु पाठ्यक्रमों की रुपरेखा

सेमिस्टर - I

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
एईएम 101:	कृषि विस्तार का परिचय	(3 क्रेडिट)
एईएम 102:	विकास हेतु सुगमता	(2 क्रेडिट)
एईएम 103:	विस्तार हेतु संचार	(4 क्रेडिट)
एईएम 104:	कृषि विकास हेतु जेन्डर को मुख्यधारा में लाना	(3 क्रेडिट)
एईएम 105:	नेतृत्व एवं प्रबंध कौशल	(3 क्रेडिट)

सेमिस्टर - II

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
एईएम 201:	ग्रामीण समाजशास्त्र	(2क्रेडिट)
एईएम 202:	कृषि व्यापार प्रबंध	(4क्रेडिट)
एईएम 203:	कृषि प्रबंधन हेतु योजना	(3क्रेडिट)
एईएम 204:	सतत कृषि विकास हेतु विस्तार	(3क्रेडिट)
एईएम 205:	परियोजना कार्य	(3क्रेडिट)

योग्यता मापदन्ड

विस्तार कर्मी जिन्होने कृषि विस्तार संबंधी क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशुसंवर्धन, मत्स्य पालन आदि, में स्नातक हैं और केन्द्र / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के सरकारों या राज्य कृषि विश्व विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत हैं, इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र है। सरकारी विस्तार कर्मियों को वरीयता दी जाएगी। आत्मा के ब्लॉक और सहायक तकनी की प्रबन्धक (बीटीएम & एटीएम), के वीकेके एसएमएस और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम के लिए पात्र है। कृषि, तत्संबंधी विषयों के स्नातक और कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी किसान संगठन में कार्यरत स्नातक, कृषि-उद्यमी और इनपुट डीलर भी पात्र है।

प्रगति

कुल 19172 उम्मीदवारों ने पीजीडीएईएम (12 बैचों में) दाखिला लिया है, जिनमें से 13,306 उम्मीदवारों ने सफलता पूर्वक डिप्लोमा पूरा कर लिया है और शेष पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। पीजीडीएईएम में प्रगति नीचे दीगई है.

31 मार्च 2019 तक पीजीडीएईएम में प्रगति

क्र.सं.	बैच	नामांकित उम्मीदवार की संख्या	उत्तीर्ण	अनुपस्थित	आंशिक रूप से पूरा	टिप्पणी
1.	1 से 11 (वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2017-18)	18160	13306	3172	1682	88.21% 2017-18 तक पास प्रतिशत (कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से)
2.	12 वाँ बैच (वित्तीय वर्ष 2018-19)	1012	द्वितीय सेमेस्टर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं			
	कुल	**19172**				
3.	13 वाँ बैच (वित्तीय वर्ष 2019-20)	14 राज्यों से 554 आवेदन प्राप्त हुए और 12 राज्यों के आवेदन प्राप्त होने हैं और 13 वें बैच के लिए अपेक्षित नामांकन 900 है।				

- 11 वीं बैच के 847 सफल आवेदकों को जुलाई 2019 में प्रमाणपत्र प्रदान किए गए है।
- 2018-19 (12वां) बैच के प्रथम सेमिस्टर की परीक्षाएं और वर्ष 2017-18 (11 वां) बैच के प्रथम और द्वितीय बैच की पूरक परिक्षाएं आयोजित की गई हैं। फरवरी 2020 के दौरान 2017-18 बैच के 126 आवेदक जिन्होंने सितंबर 2019 में सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किए हैं को प्रमाण पत्र दिए गए है। परिवर्तित पाठ्यांश को ध्यान रखते हुए सभी असफल आवेदकों को परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया गया है।
- पाठ्यांशों की समीक्षा और पी जी डी ए ई एम पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी में पाठचर्या का विकास किया जा चुका है। पाठचर्या का हिन्दी अनुवाद और वीडियों पाठों का रिकॉर्डिंग प्रगति पर है।
- वर्ष 2019-20 (13वें) बैच के लिए भर्ती प्रक्रिया नवंबर, 2019 में शुरू हुई और प्रवेश प्रक्रिया प्रगति पर है।

अफगानिस्तान में पीजीडीईएमईएम

कृषि विस्तार प्रबंधन (पीजीडीईएमई) में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा मई 2017 में दूरस्थ शिक्षा मोड में, एमएआईएल के सहयोग से मेल, अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें 68 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है इन में से 48 आवेदक पाठ्यक्रम का अध्ययन करर हे हैं। द्वितीय सेमिस्टर की परीक्षा और प्रथम सेमिस्टर की पूरक परीक्षाएं जुलाई, 2019 के अंतिम सप्ताह के दौरान संपन्न हुई। 20 सफल उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जारी करना जारी है। प्रेषण के लिए प्रमाण पत्र तैयार रखे ।

ऑनलाईन पीजीडीएइएम (मूक्स)

पाँचवें एवं छठे बैच 2018-19 में कुल 240 आवेदको ने दाखिला लिया।

- 1 जनवरी, 2020 - 31 मार्च, 2020 से 7 वींबैच का पंजी करण प्रारंभ हुआ है और - 31 मार्च, 2020 तक 1276 आवेदकों ने पंजीकृत किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए 5 वां बैच के द्वितीय से मिस्टर और 6 वां बैच के प्रथम सेमिस्टर की परीक्षाओं के परिणामों की प्रतीक्षा हैं।

प्रामाणिक क्षेत्र सलाहकार/प्रामाणिक पशुधन सलाहकार कार्यक्रम

मैनज द्वारा देश के कृषि एवं उससे संबंधित विभागों के विस्तार कार्यकारियों के लिए आवश्यकता आधारित विस्तार प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। तथापिऐसा महसूस किया जा रहा कि, मैनेज के क्षमता निर्माण कार्य क्रमों को इनफंक्शनरीज की सहायता करनी चाहिए ताकि, वे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों की सिद्धांत तकनीकों को आगे बढ़ाएं। अत: मैनेज ने कृषि व संबंधित क्षेत्रों के विस्तार अधिकारियों के लिए आई सीएआर संस्थानों / एसएयूव अन्य संस्थानों के संयोजन से 'प्रामाणिक क्षेत्र सलाहकार / प्रामाणिक पशुधन सलाहकार नामक नये कार्यक्रम को प्रस्तावित किया है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में "प्रभावी तकनीकी सलाहकारी" सेवाएं प्रदान करने और तद्वारा किसानों की क्षेत्र स्तर की समस्याओं का समाधान करने उचित तकनीकियों पर सरकारी व निजी विस्तार व्यवसायियों की मूलभूत दक्षताओं को उचित रूप से बढ़ाने के द्वारा "प्रमाणित फार्म सलाहकार / प्रमाणित पशुधन सलाहकार" के कैडर तैयार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

कार्यक्रम की संरचना

कार्यक्रम में तीन मॉड्यूल होते हैं।

मॉड्यूल-I: तीन महीने की अवधिवाले इस मॉड्यूल में क्षेत्र-विशिष्ट की नवीनतम तकनीकों तथा ई-प्लेटफार्म (मूक्स) के माध्यम से प्रबंधन के आयामों एवं महत्व पूर्ण व उभरते क्षेत्रों आदि से संबंधित विषय समाविष्ट होंगे। पठन सामग्री पाठ्य पॉवर पॉइंट और वीडियों में ही आरंभ होगा अत: इस कार्य क्रम में नामांकन करवानेवाले अधिकारियों / कर्मचारियों के नियमित कार्यों (ड्यूटी) में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। नामांकन के लिए कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना आवश्यक है।

मॉडयूल-II: मॉडयूल-I पूरा करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को आईसीएआर के संस्थानों / एसएयू / एलीट संस्थानों विस्तार कमिटी का अवश्यकता के आधार पर) में 15 दिन के सघन विशेष - कौशल - उन्मुख प्रशिक्षण हेतु उनके राज्य के भीतर अथवा बाहर भेजा जाएगा।

मॉड्यूल-III: मॉड्यूल-II की समाप्ति के बाद, प्रत्याशी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में, प्राप्त शिक्षा के अनुसार ज्ञान का अनुपालन करेंगे। प्रत्याशी को अगले एक वर्ष तक उसी संस्थान के किसी एक वैज्ञानिक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा जहाँ से उस प्रत्याशीने मॉड्यूल-II पूरा किया था। यह सहयोग (हैंडहोल्डिंग) उसे अपने प्राप्त ज्ञान / कौशलों का अपने नये उद्यम में कार्यान्वित करते समय किसी प्रकार की समस्या आने पर तकनी की मार्गदर्शन के रूपमें दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्याशी को क्षेत्र-विशेषके व्यावहारिक पहलुओं को समझने में आसानी होगी। मॉडयूलIII की समाप्तितक, प्रत्याशी अपने क्षेत्र (फील्ड) की समस्याओं का निवारण करने में सक्षम हो जएंगे और किसानों को बेहतर सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

तीनों मॉड्यूल पूरा करेन के बाद प्रत्याशी की सक्षमताओं का मूल्यांकन उसकी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा और उसे संबंधित आईसीएआर / अन्य संगत सलाहकार/प्रमाणिक पशुधन सलाहकार घोषित कर दिया जाएगा।

अपेक्षित आउटकम

इस कार्यक्रम को पूरा करने के उपरांत, प्रत्याशी को एक विशेष / विशिष्टता के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 'प्रामाणिक क्षेत्र सलाहकार' के रूप में घोषित करने के बाद, मै ने ज उनके नामों को अपनी वेबवाइट पर दर्शाएगा कि अन्य भागीदार उनकी क्षमताओं से अवगत हो कर सलाहकार - सेवाएं प्राप्ति कर सकें। इस कार्यक्रम के द्वारा, विभाग के भितर विविध विषयों / विशिष्टताओं, संबंधी विशेषज्ञों के एक संवर्ग (काडर) का सृजन करने का अवसर मिलेगा ताकि उन सलाहकारों की क्षमताओं में वृद्धि कर के उन्हें बेहतर तकनीकी सलाहकार बनाया जा सके और वे किसानों की क्षेत्रगत समस्याओं का बेहतर निवारण कर सकें।

नामंकन हेतु पात्रता के मानदंड

55 वर्ष तक की आयुवाले बीएससी कुषि, बागवती, पशुपालन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के स्नातक कोई भी विस्तार अधिकारी / कृषि उद्यमी जिसे कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो इस के लिए योग्य है। कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी होनी चाहिए।

शुल्क :

सरकारी विभागों के तहत कार्यरत विस्तार फंक्शनरी केलिए कोर्स शुल्क, 5,000/- रू. प्रति प्रत्याशी होगा जब कि निजी क्षेत्र केकृषि उद्यमियों व प्रत्याशियों का शुल्क 15,000/- प्रति व्यक्ति होगा।

वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रगति :

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान कार्यक्रम की प्रगति निम्नानुसार है

1. मॉड्यूल- III का मूल्यांकन (2018-19) प्रगति पर
2. सभी तीनों मॉड्यूलों को संपूर्ण करने के संबंध में नामित / राज्य विभाग को पत्र भेजे गए है और प्रमाणित फसल / पशुधन सलाहकार को आकादमियों, विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण और किसान के लिए विस्तार संबंधी उनके क्रिया कलापों में उपयोग करने को सूचित किया गया है।
3. अकादमिक वर्ष 2019-20 बैच के लिए कुल 228 आवेदक पंजीकृत हुए है।
4. 12 विशेषताओं के लिए नामांकन प्राप्त हुए। मॉडयूल- II के तेरह कार्यक्रम (15 दिनों का प्रशिक्षण) संबद्ध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं में आयोजित किए जाएंगे। (जैवी कृषि को दो बैचों में आयोजित किया गया)। मॉडयूल - III प्रगति पर है।
5. दस प्रमाणित फार्म - पशुधन सलाहकार प्रशिक्षार्थियों की सफल कहानियों को मैनेज वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।
6. औषधीय और सुगंधीय पौधे, फल और मुर्गीपालन पर प्रमाणित फार्म सलाहकार / पशुधन सलाहकारों संबंधी सूचना मैनेज के वेबसाईट पर दर्शाया गया है।
7. प्रमाणित फार्म / पशुधन सलाहकार कार्यक्रम के अनुभवों को दर्ज करते हुए तीन वीडियो को मैनेज मूक्स लैब में रिकार्ड किया गया और उन्हें मैनेज 'यूट्यूब' चैनेल पर अपलोड किया गया।

8. पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में कुल रु.12,80,000 (बारह लाख अस्सी हजार मात्र) की राशि संकलित की गयी और उसे मैनेज एकाउन्ट में जमा कर दिया गया।

9. अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए अब तक कुल 89 आवेदन प्राप्त हुए है।

10. वर्ष 2020-21 बैच के लिए अब तक कुल रु.2,30,000 (दो लाख तीस हजार की राशि मात्र) पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ और इस राशि को मैनेज लेखा में जमा कर दिया गया है।

मॉड्यूल का विवरण - विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में आयोजित किया जाता है

क्र.सं.	आईसीएआर संस्थान	विशेषज्ञता	अनुसूची
1.	आई सी ए आर भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ, उत्तर प्रदेश	बीज विज्ञान	23 सितंबर से 07 अक्तूबर, 2019
2.	आई सी ए आर भारतीय कृषिप्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तरप्रदेश	जैविक कृषि	बैच- I: 10 - 24 अक्टूबर, 2019, बैच- II: 05 - 19 दिसंबर, 2019
3.	आई सी ए आर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तरप्रदेश	दलहन	10 - 24 अक्टूबर, 2019
4.	आई सी ए आर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना	चावल	10 - 24 अक्टूबर, 2019
5.	आई सी ए आर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	सब्जी	10 - 24 अक्टूबर, 2019
6.	आई सी ए आर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड, केरल	मसाले	11 - 25 नवंबर, 2019
7.	आई सी ए आर भारतीय फल अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक	फल	12 – 26 नवंबर, 2019
8.	आई सी ए आर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान	भेड़	21 नवंबर - 05 दिसंबर 2019
9.	केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, उत्तरप्रदेश	बकरी	26 नवंबर - 10 दिसंबर 2019
10.	केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, मेरठकैंट, उत्तरप्रदेश	मवेशी	03 - 17 दिसंबर, 2019
11.	पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, तेलंगाना	पोल्ट्री	03 - 17 दिसंबर, 2019
12.	आई सी ए आर भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना	कदन्न	22 जनवरी - 05 फरवरी, 2020

स्नातकोत्तर कृषि-भंडारण प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएडव्ल्यूएम)

कृषि विकास में भण्डारगाह के महत्व को समझते हुए, मैनेज ने कृषि-भण्डारण प्रबंधन पर एक शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किया है जिसे कृषि-भण्डारण प्रबंधन स्नातकोत्तर कृषि भण्डारण प्रबंध डिप्लोमा कहा जाता है। कार्यक्रम एमओओसीएस प्लैटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन की चलाया जाता है।

उद्देश्य

वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभ किए गए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भण्डारगाहों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की क्षमता वाले भण्डागाहों के पेरोवरों के एक पूल का तैयार करना हैं ।

पाठ्यक्रम संरचना और सामग्री

पाठ्यक्रम में कृषि-भण्डारगाहके विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम सामग्री दो सेमेस्टरों में पेश की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल प्रत्येक विषय पर पठन सामग्री छात्रों को प्रदान की जाती है। नामांकित उम्मीदवारों के लिए आसानी से सीखने की सुविधा हेतु इस कार्यक्रम की सामग्री वीडियो व्याख्यान के माध्यम से भी प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा के अलावा प्रत्येक विषय से संबंधित असाइनमेंट को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नामांकित उम्मीदवारों को फील्ड एक्सपोजर प्रदान करने के लिए, एक्सपोजर विजिट का प्रावधान है, जिससे उम्मीदवारों से भण्डारगाह का दौरा करने और प्राप्त अनुभव के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने की उम्मीद की जाती है। व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक्सपोज़र दौरा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है।

प्रत्येक वर्ष दो नए बैचों की घोषणा की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान घोषित पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में कुल 90 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है।

6. सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का सहयोग

ज्ञान प्रबंधन केंद्र, आईसीटी एवं मास मीडिया केन्द्र का कार्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अवधारणाओं को विकसित करने तथा सूचना प्रबंधन रणनीति का संचालन करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की क्षमता को बढ़ाने आदि पर केंद्रित है।

संस्थान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता 150 कंप्यूटर सिस्टमों के माध्यम से प्रदान की जाती है, जो 100 एमबीपीएस और 50 एमबीपीएस की दो लीजड लाइनों से 24 घंटे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हैं। परिसर वाई-फाई सक्षम है। विभिन्न संस्थानों के साथ संचार की सुविधा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध है। मैनेज प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों, परियोजनाओं और प्रकाशनों की जानकारी वेबसाइट www.manage.gov.in पर नियमित रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अद्यतन की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और अन्य कार्यक्रमों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की जानकारी और अपडेट्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएँ

इस वर्ष के दौरान, आईसीटी विषय वस्तु जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ई-विस्तार, ई-गवर्नेंस तथा परियोजना प्रबंधन कौशल आदि में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एक कार्यशाला ई-एनबीएटी(eNBAT)पर आयोजित की गई थी।

अनुसंधान परियोजनायें

1. प्रो-सॉइल परियोजना

मैनेज जीआईजेड के साथ "भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा संरक्षण और पुनर्वास (प्रो-सॉइल)" परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के चयनित क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता सहित निम्नीकृत मृदा (डीग्रेडड सोयल) के संरक्षण और पुनर्वास के लिए सतत दृष्टिकोण लागू करना है। कुल मिलाकर 43.000 हेक्टेयर क्षेत्र जो पहले से वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत रहा है, महाराष्ट्र के पांच जिलों (अहमदनगर, अमरावती, धूले, जालना और यावतमल) और मध्य प्रदेश के दो जिलों (बालाघाट और मंडला) को इसमें शामिल किया गया है। नेशनल कंसोर्टियम फैसिलिटेटिंग एजेंसी (एनसीएफए), स्तर पर मैनेज राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और समग्र नेटवर्क प्रबंधन के माध्यम से प्रो-सॉइल सहयोग के अंतर्गत परिकल्पित नेटवर्क दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान कर रहा है। परियोजना की अवधि मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

2. केएफडब्ल्यू परियोजना में आईसीटी सक्षम सलाहकार सेवाओं का कार्यान्वयन

नाबार्ड रणनीतिक रूप से केएफडब्ल्यू के सहयोग से जीआईजेड (GIZ) के साथ साझेदारी में भारत-जर्मन द्विपक्षीय संबंध के भाग के रूप में 'डीग्रेडेड मृदा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के पुनर्स्थापन के लिए वाटरशेड विकास का समाकलन' नामक महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़ा है। किसानों को गुणवत्ता युक्त सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकें, इसके लिए मैनेज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना के केएफडब्ल्यू मृदा परियोजना क्षेत्रों में आईसीटी (ICT) सक्षम सलाहकार सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए जीआईजेड प्रो-सॉइल मृदा परियोजना के अंतर्गत पहले से बनाए गए अभिनव आईसीटी सक्षम सलाहकार प्लेटफॉर्म "नाइस (NICE) प्रणाली" को लागू करता आ रहा है। केएफडब्ल्यू-नाबार्ड की परिकल्पना 31 जिला के 122 वाटरशेड गांवों में 24560 किसानों को शामिल करते हुए पांच राज्यों में आईसीटी आधारित कृषि-सलाहकार प्लैटफार्म को लागू करने की है।

मौसम और निदानकारी क्षेत्र दौरे के दौरान पहचान किए गए मामलों के आधार पर परियोजना क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों पर परामर्श जयार किया जाता है। एसएमएस, वीडियो यूआरएल, पोस्टरों और दस्तावेजों सहित एक बहुउद्देशीय सलाहकार सेवा तैयार की गई तथा नाइस एसएसएम पोर्टल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया गया। उत्पादन, संरक्षण और फसल-कटाई उपरांत के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली फसल बुलेटिन को स्थानीय भाषा में तैयार और प्रकाशित किया गया था, जिसे भविष्य में किसानों को आवश्यक परामर्श प्रदान करने के लिए तैयार संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियों में वितरित किया जाएगा। मैनेज ने अपने यू ट्यूब चैनल में खेती के कई पहलुओं पर कई वीडियो प्रकाशित किए हैं।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित इन वीडियो यूआरएल और अन्य वीडियो यूआरएल को सीआरपी के साथ नाइस एसएसएम पोर्टल के माध्यम से भी साझा किया गया था। सीआरपी द्वारा फसल के विभिन्न चरणों के अनुसार रंगीन पोस्टरों को प्रिंट किया गया था तथा उन्हें गांव के ज्ञान केंद्रों और उन स्थानों पर चिपकाया गया था जहां किसान अपने कार्य के लिए एकत्रित होते हैं। सप्ताह में दो बार आईएमडी द्वारा प्रकाशित होने वाले जिला कृषि सलाहकार सेवा बुलेटिन को भी सीआरपी के साथ नाइस एसएसएम पोर्टल के माध्यम से साझा किया गया। उपरोक्त के अलावा, किसानों की प्रतिक्रिया, उनके सवालों और एसएयू पर आधारित नियमित क्षेत्र की समसामयिक समस्याओं पर आवश्यकता के आधार पर पोस्टर तैयार किए गए और किसानों तक पहुंचाया गया। 2484 सलाहों के रूप में किसानों को कुल 1868378 एसएमएस भेजे गए। परियोजना की अवधि दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।

एमओओसी (MOOCs) ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम

एमओओसी (MOOCs): मैनेज ने तेजी से विकास कर रहे तथा विविधतापूर्ण कृषि सेक्टर में कृषि विस्तार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ऑनलाइन ई-लर्निंग कार्यक्रम की पहल की है,जिसे मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC), कहा जाता है। कृषि भंडारगाह (गोदाम) प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएडब्ल्यूएम) एमओओसी (MOOCs) पर एक वर्ष का ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो न केवल भारतीय अधिकारियों के लिए आरंभ किया गया है, बल्कि विश्वव्यापी है। पीजीडीएडब्ल्यूएम एमओओसी में शिक्षार्थी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो, पीपीटी, व्याख्यान नोट, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है। प्रत्येक सत्र के अंत में, छात्र असाइनमेंट जमा करते हैं और अंतिम परीक्षा ऑनलाइन देते हैं।

7. पुस्तकालय, प्रलेखन एवं प्रकाशन

पुस्तकालय संबंधित क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने वाली सेवाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुसंधान गतिविधियों और संस्थान के अन्य कार्यक्रमों में सहायता करता है। पुस्तकालय संसाधनों में संस्थान के प्रमुख क्षेत्रों पर पुस्तकें, जर्नल, रिपोर्ट, लेख, डेटाबेस शामिल हैं। पुस्तकालय ऑनलाइन डेटाबेस को सब्सक्राइब करता है यथा 'कमॉडिटीस' जो कीमतों, बाजार इंटेलीजेंस, फसलों के पूर्वानुमान तथा 'इंडिया स्टैट्स' जो भारत की सांख्यिकीय जानकारी तक पहुँच प्रदान करती है। 'प्रॉक्वेस्ट' एक ई जर्नल डेटाबेस है। इन डेटाबेस तक संकाय, कर्मचारियों और छात्रों की पहुँच होती है।

संदर्भ और साहित्य खोजने की सेवाएं, अनुरोध पर प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालय संग्रह में जोड़े गए नए संसाधनों और जर्नल में नवीनतम लेखों के बारे में सूचित करने के लिए संकाय को आवधिक अलर्ट भेजे जाते हैं। परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रमुख क्षेत्रों पर संकाय को सार और सूचीकरण सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। दैनिक आधार पर ईमेल के माध्यम से पुस्तकालय संकाय और छात्रों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर समाचार अलर्ट भेजा जाता है। पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकों और लेखों के डेटाबेस को बनाए रखा जाता है।

प्रलेखन और प्रकाशन

विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से कृषि विस्तार और संबद्ध क्षेत्रों, दृष्टिकोणों, विस्तार में अनुसंधान की जानकारी का प्रसार किया जाता है।

- जर्नल ऑफ़ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एक अर्ध-वार्षिक प्रकाशन है जिसमें कृषि विस्तार और संबद्ध क्षेत्रों के लेख प्रकाशित होते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो अंको प्रकाशित और प्रसारित किया गया.
- विस्तार डाइजेस्ट कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्तमान चिंताओं के चयनित विषयों पर जानकारी का संश्लेषण है। इस अवधि के दौरान "कीट प्रबंधन के लिए पारिस्थितिक रूप से स्थायी रणनीति" पर एक अंक प्रकाशित किया गया था।
- मैनेज बुलेटिन एक द्वि-मासिक समाचार पत्र है, जो मैनेज प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, योजनाओं के कार्यान्वयन, घटनाओं आदि पर अद्यतन को शामिल करता है।
- मैनेज अंतर्राष्ट्रीय ई-बुलेटिन, एक मासिक समाचार पत्र है जो फ्यूचर इंडिया त्रिकोणीय प्रशिक्षण (एफटीएफ-आईटीटी) कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं को रिपोर्ट करता है।
- स्पाइस, पीजीडीएम (एबीएम) का एक त्रैमासिक समाचार पत्र है जो कैंपस समाचार, उद्योग-इंटरफ़ेस कार्यक्रम, घटनाओं और छात्रों के लेखों को प्रकाशित करता है।

विभिन्न केंद्रों से प्रकाशन

चर्चा पत्र

1. मोहित कुमार, सुचिरदीप्त भट्टाचार्जी और सरवणन राज (2019). कृषि के भविष्य को पुन: आकार देना: युवा और सामाजिक मीडिया परिप्रेक्ष्य। चर्चा पेपर 6, मैनेज, सीएईआईआरए.

2. अंजना, एस.आर.सुचिरदीप्त भट्टाचार्जी और सरवणन राज (2019). खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ग्रामीण समुदाय के लिए सूचना स्रोत और जागरूकता स्तर। चर्चा पत्र 7. मैनेज, सीएईआईआरए (CAEIRA).

3. शेख शुबीना, सुचिरदीप्त भट्टाचार्जी और सरवणन राज (2019). भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के पशुधन विस्तार पेशेवरों की मुख्य दक्षताओं का आकलन। चर्चा पत्र 8. मैनेज, सीएईआईआरए (CAEIRA).

4. नागेश, जी और सरवणन राज (2019). कृषि विकास और विकास पर आईसीटी का प्रभाव: कर्नाटक क्षेत्र के प्रकरण का अध्ययन, चर्चा पत्र 9. मैनेज, सीएईआईआरए (CAEIRA).

5. अनुपम आनंद और सरवणन राज (2019). एग्रीटेक स्टार्टअप: भारतीय कृषि में आशा की किरण। चर्चा पत्र 10. मैनेज, सीएईआईआरए (CAEIRA).

6. विंसेंट. एवं बालासुब्रमणि एन. (2019). जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए विस्तार परामर्श सेवाएं- अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश, भारत का एक मामला। चर्चा पत्र, मैनेज, सीसीए (CCA).

पुस्तकें और रिपोर्ट

1. मानव आवासों में कीट/वेक्टर प्रबंधन के लिए विस्तार दिशानिर्देश। (2019)

2. भारत में कृषि बीमा को किसान-हितैषी और जलवायु अनुकूल बनाने - की ओर बढ़ते कदम - रिपोर्ट। (2019)

3. कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा: नवाचार - आरकेवीवाई - रफ्तार:स्टार्टअप कृषिव्यवसाय इन्क्यूबेशन कार्यक्रम (सैप)(2020)को बढ़ावा देना।

4. कृषि-स्टार्टअप: विचारों को प्रवाह - आरकेवीवाई - रफ्तार: कृषि उद्यमिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम (एओपी) (2020)

5. जिला कीट प्रबंधन (डीपीएमपी): पोस्ट परियोजनानंतर प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (2020)

6. निमिषा मित्तल, रशीद सुलेमान वी और एन. बालसुब्रमणि (2019). डीएईएसआई (DAESI) पर अभ्यास नोट - डीएईएसआई कार्यक्रम, दक्षिण एशिया में कृषि विस्तार (एईएसए) के माध्यम से भारत में कृषि इनपुट डीलरों का क्षमता विकास।

8. राजभाषा की प्रगति

मैनेज संघ की राजभाषा के कार्यान्वयन दिशा में कटिबद्ध है। एक प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते मैनेज अपने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में प्रदान करने पर फोक्स करते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान चार प्रशिक्षण सामग्रियों को द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रतिभागियों को प्रदान किया गया है। कृषि विस्तार नवोन्मेशन सुधार और कृषि उद्यमिता केन्द्र के तहत छः अनुसंधान रिपोर्टों का संक्षेप हिन्दी भाषा में भी तैयार कर मैनेज वेब साईट पर अपलोड किया गया है। शहरी कृषि पर न्यूज लेटर का हिन्दी अनुवाद कर स्टेकहोलडरों को आबंटित किया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखा को द्विभाषी रूप में तैयार कर संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत किया गया है।

मैनेज की नियमित गतिविधि के रूप में मैनेज राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट को राजभाषा प्रभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय राजभाषा विभाग, साऊथ ब्लॉक, बैंगलूरु को भेजा गया है। राजभाषा नियमों के अनुसार 'क और ख' क्षेत्रों के तहत आने वाले राज्यों के साथ मैनेज का पत्राचार द्विभाषी रूप में किया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन के प्रयास किए जाते है। आंतरिक मिसलों टिप्पणों को हिन्दी में लिखने के दौरान हिन्दी में अत्यधिक काम करने वाले कर्मचारियों को और अनुभागों को पुरस्कृत किया गया है। मैनेज के कर्मचारियों को दो समूहों में बॉटकर नियमित राजभाषा तिमाही कार्याशाला के अलावा हिन्दी सीखने के लिए दो कक्षाएं चलाई जा रही हैं। मैनेज में हर महीने हिन्दी का एक लघु चित्र दिखाने के बाद, चित्र में उपयोग की गयी शब्दावली पर चर्चा की जाती है। इस नवीन कार्य से मैनेज संकाय, अधिकारी एवं कर्मचारियों की बोलचाल की हिन्दी में सुधार लाने की अपेक्षा की जाती है।

हैदराबाद-सिकंदराबाद नराकास - 4 (के.स.का.) द्वारा 100 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय के वर्ग में मैनेज को उत्तम कार्यान्वयन कार्यालय की उपाधि से सम्मानित किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मैनेज में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 4 से 19 सितंबर, 2019 तक किया गया और इस अवधि में राजभाषा की प्रगामी प्रयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। कर्मचारियों एवं पी जी डी एम (एबी बी एम) छात्रों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विजेताओं को हिन्दी दिवस समारोह में पुरस्कार वितरण किया गया है।

9. प्रशासन एवं लेखा

मैनेज के सामान्य पर्यवेक्षण माननीय केंद्र कृषि मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में महापरिषद द्वारा किया जाता है। मैनेज के प्रभावी प्रबंधन और प्रशासन के लिए महापरिषद संपूर्ण नियंत्रण और नीति निर्देशन करती है। माननीय कृषि राज्य मंत्री तथा सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दोनों महापरिषद के दो उपाध्यक्ष है। मैनेज के महापरिषद का गठन **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

महापरिषद के निर्देश और संपूर्ण नियंत्रण के अनुरूप, मैनेज का कार्यकारी परिषद, नीति संबंधी विषयों और उप नियम व बै-लॉस के अनुसार संस्थान की गतिविधियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी परिषद का गठन **परिशिष्ट-II** में संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति होती है और वे संस्थान की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के जिम्मेदार होते हैं। संकाय सदस्य, प्रशासन और इंजीनियरिंग विंग महानिदेशक की सहायता करते हैं। मैनेज के संकाय और अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-III** में दी गई है।

निधि

प्रत्येक वर्ष भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग मैनेज को अनुदान सहायता देता है। स्थापना एवं प्रशासन पर हुए साठ प्रतिशत व्यय को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी कीगयी अनुदान राशि मे से लिया जाता है तथा शेष चालीस प्रतिशत व्यय को मैनेज स्वयं के निधि से करता है। तथापि, मैनेज के इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरे व्यय को भारत सरकार के निधि से व्यय किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के लिए के लिए 5 प्रथम अपील और 1 द्वितीय अपील सहित 50 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। उनका जवाब समय पर आवेदकों को भेजा गया।

सतर्कता के मामले

वर्ष के दौरान मैनेज के कर्मचारियों के खिलाफ कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं था।

बैठकें

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई:

कार्यकारी परिषद

5 अप्रैल 2019 को मैनेज का 72 वीं कार्यकारी परिषद की बैठक और 12 फरवरी 2020 को कृषि भवन, नईदिल्ली में 73 वीं बैठक श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से., सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत

सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। परिषद ने संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा की।

अकादमिक समिति की बैठक

मैनेज की अकादमिक समिति की 24 वीं बैठक 27 फरवरी, 2020 को मैनेज, हैदराबाद में संपन्न हुई। श्रीमती जी. जयलक्ष्मी, भा.प्र.से., महानिदेशक, मैनेज ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अकादमिक समित के सदस्य में कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से नामिती और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, कृषि अनुसंधान संस्थानों से नामी वैज्ञानिक / अनुसंधान कर्ता, प्रबंध संस्थानों के प्रोफेसर, ई ई आई के प्रतिनिधि, और मैनेज के संकाय सदस्य सम्मिलित है। महानिदेशक, मैनेज के संकाय सदस्य सम्मिलित है। महानिदेशक, मैनेज ने वर्ष 2019-20 के दौरान मैनेज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान गतिविधियों और शिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में बताया और वर्ष 2020-21 के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम जो कृषि विस्तार व्यवसायियों के प्रशिक्षण और दक्षता आवश्यकताओं की पूर्ती करते है के बारे में भी संक्षिप्त में बताया। समिति ने मैनेज की अकादमिक गतिविधियों की समीक्षा की और अकादमिक कैलेंडर 2020-21 को अनुमति प्रदान की ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

मैनेज की महापरिषद के सदस्य

नियम सं. 3(ए)	महापरिषद का गठन	क्र.सं	सदस्य का नाम एवं पता
i	मैनेज का अध्यक्षः भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री जो मैनेज से संबद्द होंगे।	1	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
ii	मैनेज के दो उपाध्यक्षः: कृषि राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	2	श्री पुरुषोत्तम रुपाला, माननीय कृषि राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	3	डॉ. संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 115, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001 E-mail: secy-agri@gov.in
iii	एक व्यक्ति गैर अधिकारी जो भारत की संस्थाओं में कृषि विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों - सदस्य के रूप में मैनेज के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे।	4	श्री रामसिंह परमार, अध्यक्ष गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल), अमूल डेयरी रोड, पोस्ट बक्स नं. 10, आनंद - 388 001, गुजरात
iv	तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने कृषि विकास के क्षेत्र में तथा संबंधित विषयों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।	5	श्री गोली मधुसूदन रेड्डी, S/o श्री नारायण रेड्डी, हाउस नं.: 7-8-119, श्रीनगर कॉलोनी, पानागल रोड, नालगोंडा, तेलंगाना - 508 001
		6	श्री के.वी. कन्नन S/o श्री एम. विश्वनाथन, नं. 1, ओममपुलियूर रोड, जिला - कुददलूर, कट्टामन्नारकोली - 608 301, तमिलनाडु
		7	श्री पी. वी. सुब्रमण्यम वर्मा, S/o श्री वेंकट पती राजू, डोर नं.1/176, पंचायत ऑफिस रोड, ककारापारु, पेरावली मंडल, पश्चिम गोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश - 534 331
	पदेन सदस्य		
v	महानिदेशक, एन आई आर डी एवं पी आर	8	डॉ. डब्ल्यू आर. रेड्डी, भा.प्र.से. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
vi	महानिदेशक, एनआईएएम	9	डॉ. पी. चंद्रशेखरा, महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) कोटा मार्ग, बंबाला, संगनेर के पास जयपुर - 303 906

vii	महानिदेशक, आईसीएआर	10	डॉ. त्रिलोचन महापात्रा सचिव (डीएआरई) व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 011 फोन नं.: (कार्यालय) 011 - 23382629, 23386711; फैक्स नं.: 011-23384773 E-mail: dg.icar@nic.in
viii	क) अपर सचिव ख) सयुक्त सचिव जो विस्तार के प्रभारी हैं ग) भारत सरकार के मत्रालय/विभाग में वित्त सलाहकार जो मैनेज से संबद्ध हैं	11	श्रीमती वसुधा मिश्रा, भा.प्र.से., अपर सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001 E-mail: asc-agri@gov.in
		12	श्री आतिश चंद्रा, भा.प्र.से. संयुक्त सचिव (विस्तार/आईटी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं. 247-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001 E-mail: catish@ias.nic.in
		13	श्री बी. प्रधान, भा.प्र.से. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
ix	कृषि आयुक्त भारत सरकार, कृषि, सहकारिता विभाग, एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली	14	कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
x	भारत सरकार के योजना आयोग विभाग के सचिव या नामित सदस्य जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के नीचे न हों।	15	सचिव, योजना आयोग भारत सरकार, योजना भवन नई दिल्ली - 110 001
xi	राज्य सरकार के चार सचिव / संघ राज्य - क्षेत्र के कृषि उत्पादन के प्रभारी (चक्रानुक्रम में) या उनके नामिती जो राज्य सरकार के उप सचिव पद से नीचे के न हों।	16	प्रधान सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार, कमरा सं. 510, मंत्रालय एनेक्स, मुंबई - 400 032, महाराष्ट्र
		17	प्रधान सचिव (कृषि), मध्य प्रदेश सरकार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय, कमरा नंबर 302, भोपाल 462 001, मध्य प्रदेश
		18	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव (कृषि), तमिलनाडु सरकार, कृषि विभाग सचिवालय, सेंट जॉर्ज फोर्ट, चेन्नई - 600 009, तमिलनाडु
		19	प्रधान सचिव (कृषि), गुजरात सरकार, नया सचिवालय परिसर, ब्लॉक- 5, प्रथम तल, गांधी नगर - 382 010, गुजरात

xii	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के दो कृषि निदेशक (चक्रानुक्रम द्वारा देश के अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने हेतु); या उनके नामिती जो कृषि अपर निदेशक या उसके समतुल्य अधिकारी के पद से नीचे के न हों।	20	कृषि निदेशक, बिहार सरकार, कृषि विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना - 800 015, बिहार
		21	कृषि निदेशक, असम सरकार, कृषि विभाग, खानपरा, गुवाहाटी - 781 022, असम
xiii	मैनेज के महानिदेशक जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये है। (पदेन सदस्य व सदस्य साचिव)	22	श्रीमती वी. उषा रानी, भा.प्र.से. (23/10/2019 तक) श्रीमती जी. जयलक्ष्मी, भा.प्र.से. (24/10/2019 से) महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030 तेलंगाना
xiv	कृषि विश्वविद्यालय के दो उप -कुलपति (चक्रमानुक्रम द्वारा) या उनके नामिती जो निदेशक पद से नीचे के न हों। (पदेन सदस्य)	23	उप कुलपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर
		24	उप कुलपति, डीएयू दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, दंतिवाड़ा, बनासकांठा, गुजरात

परिशिष्ट - II

मैनज की कार्यकारी परिषद के सदस्य

क्र.सं	महापरिषद का गठन	क्र.सं	सदस्य का नाम एवं पता (अध्यक्ष, अधिकारी एवं गैर-अधिकारी सदस्य)
5.I (i)	**पदेन सदस्य**		
a)	सचिव (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण) कृषि सहकारिता मैनेज के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य परिषद के उपाध्यक्ष होंगे	1	डॉ. संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं. 115, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001 E-mail: secy-agri@gov.in
b)	भारत सरकार के मंत्रालय / विभाग में विस्तार के प्रभारी अपर सचिव जो मैनेज से संबंद्ध है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष होंगे	2	श्रीमती वसुधा मिश्रा, भा.प्र.से. अपर सचिव कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं. 134, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001, E-mail: asc-agri@gov.in
c)	महानिदेशक, मैनेज	3	श्रीमती वी. उषा रानी, भा.प्र.से. (23/10/2019 तक) श्रीमती जी. जयलक्ष्मी, भा.प्र.से. (24/10/2019 से) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), राजेन्द्रनगर , हैदराबाद – 500 030
d)	भारत सरकार के मंत्रालय / विभाग में मैनेज के विस्तार एवं वित्त सलाहकार के प्रभारी संयुक्त सचिव होंगे	4	श्री आतिश चंद्रा, भा.प्र.से. संयुक्त सचिव (विस्तार/आईटी) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं. 247-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001 E-mail: catish@ias.nic.in
		5	श्री बी. प्रधान, भा.प्र.से. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001 E-mail: b.pradhan@nic.in
e)	<u>गैर-अधिकारी सदस्य</u> दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने कृषि विकास के क्षेत्र में / संबंधित विषयों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हो उन्हें भारत सरकार द्वारा महापरिषद में से नामित किये जाते है	6	श्री गोली मधुसूदन रेड्डी S/o श्री नारायण रेड्डी, हाउस नं.: 7-8-119, श्रीनगर कॉलोनी, पानागल रोड, नालगोंडा, तेलंगाना - 508 001
		7	श्री के.वी. कन्नन S/o श्री एम. विश्वनाथन, नं. 1, ओममपुलियूर रोड, जिला - कुददलूर, कट्टामन्नारकोली - 608 301 तमिलनाडु

f)	एक सदस्यों को महा परिषद द्वारा महा परिषद के गैर अधिकारी सदस्यों में से नामित किया जाएगा	8	श्री रामसिंह परमार, अध्यक्ष गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल), अमूल डेयरी रोड, पोस्ट बक्स नं. 10, आनंद - 388 001, गुजरात E-mail: gcmmf@amul.coop, chairman@amul.coop

परिशिष्ट - III

महानिदेशक

1.	**श्रीमती वी. उषा रानी, भा. प्र. से.(23/10/2019 तक)** **श्रीमती जी.जयलक्ष्मी,भा.प्र.से. (24/10/2019 से)**

अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची

2.	**डॉ. पी. चंद्रशेखरा (प्रतिनियुक्ति पर)** निदेशक (कृषि विस्तार) (वर्तमान में एन आई प एम-जयपुर के साथ प्रतिनियुक्ति पर)
3.	**डॉ. के.आनंद रेड्डी** निदेशक (मा.सं.वि.)
4.	**डॉ. सरवणन राज** निदेशक (कृषि विस्तार)
5.	**डॉ. जाबिर अली** निदेशक
6.	**डॉ.के. सी. गुम्मागोलमठ** निदेशक (एम & ई)
7.	**डॉ. के. एन. रवि कुमार (प्रतिनियुक्ति पर)** निदेशक (कृषि विपणन)
8.	**डॉ. एन. बालसुब्रमणी** निदेशक (सी सी ए)
9.	**डॉ. एम. ए. करीम** उप निदेशक (कृषि विस्तार)
10.	**डॉ. जी. जया** उप निदेशक (मा.सं.वि.)
11.	**डॉ. लक्ष्मी मूर्ति** उप निदेशक (प्रलेखन)
12.	**श्री श्रीधर खिस्ते** उप निदेशक (प्रशासन)
13.	**डॉ.शैलेन्द्र** उप निदेशक (बीएस)
14.	**डॉ. वीनिता कुमारी,** उप निदेशक (जेंडर स्टडीज)
15.	**डॉ. महंतेश शिरूर (प्रतिनियुक्ति पर)** उप निदेशक (कृषि विस्तार)

16.	**डॉ. बी. रेणुका रानी** सहायक निदेशक (एनआरएम)
17.	**श्री जी. भास्कर** सहायक निदेशक (Sr. Scale)
18.	**डॉ. पी. लक्ष्मी मनोहरी** सहायक निदेशक (Sr. Scale)
19.	**डॉ. अत्तलूरी श्रीनिवासाचार्युलु** प्रोग्राम ऑफीसर
20.	**डॉ. शाहजी संभाजी फंड** सहायक निदेशक (एलाईड एक्सटेन्शन)
21.	**डॉ. बी. वेंकट राव** उप निदेशक (क्षेत्र समन्वयक)
22.	**श्री सी. एच. एन. एम. राव** सहायक लेखा अधिकारी
23.	**डॉ. जी. राधा रूक्मिणी** चिकित्सा अधिकारी
24.	**श्रीमती एन. उषा रानी** महानिदेशक के निजी सचिव
25.	**श्री पी. जॉन मनोज** सहायक इंजीनियर (सिविल)
26.	**श्री के. वेंकटेश्वर राव** कम्प्यूटर प्रोग्रामर
27.	**डॉ. ए. कृष्णा मूर्ति** प्रलेखन सहायक
28.	**डॉ. के. साई महेश्वरी** अनुसंधान सहायक
29.	**डॉ. के. श्रीवल्ली** वरिष्ठ अनुवादक
30.	**डॉ. पी. कनक दुर्गा** अनुसंधान सहायक
31.	**डॉ. देशमुख सागर सुरेन्द्र** प्रशिक्षण सहायक
32.	**श्री ई. नागभूषणम** भंडार अधिकारी

33.	**श्री ई. राजशेखर** कार्यालय अधीक्षक
34.	**श्री टी. नागराजु** कार्यालय अधीक्षक
35.	**श्री सुनील कुमार** मेस मैनेजर
36.	**श्रीमती वी. मंगम्मा** वरिष्ठ लेखा अधिकारी
37.	**श्री के. जगन मोहन राव** रिसेप्शनिस्ट कम केरटेकर
38.	**श्रीमती पी. भारती रानी** वरिष्ठ आशुलिपिक
39.	**श्रीमती बी. रमनी** वरिष्ठ आशुलिपिक
40.	**श्रीमती के. उमा महेश्वरी** वरिष्ठ आशुलिपिक
41.	**श्रीमती बी. मीनाक्षी** वरिष्ठ आशुलिपिक
42.	**श्री बी. चक्रधर राव** ईडीपी सहायक (EDP)
43.	**श्री एम. श्रीनिवास राव** ईडीपी सहायक (EDP)
44.	**श्री एम. वेणुगोपाल** ईडीपी सहायक (EDP)
45.	**श्री के. उदय वर्मा** टेलिफोन ऑपरेटर
46.	**श्री वीरय्या** कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
47.	**डॉ. वहीदा मुनावर** कनिष्ठ लेखाकार
48.	**श्री राम मूर्ति** कोषपाल
49.	**श्री गिर्जेश जोशी** हाउस कीपर

50.	**श्री एम. शिव कुमार** कनिष्ठ लेखाकार
51.	**श्रीमती जी. संध्या रानी** प्रवर श्रेणी लिपिक
52.	**श्रीमती एन. आशालता** वरिष्ठ आशुलिपिक
53.	**श्रीमती पी. ज्योति** कनिष्ठ आशुलिपिक
54.	**श्रीमती एम. भाग्यलक्ष्मी** सहायक कोषपाल
55.	**श्रीमती के. कमला** प्रवर श्रेणी लिपिक
56.	**श्री टी. फणि कुमार** कनिष्ठ आशुलिपिक
57.	**सुश्री ए. रोनिता** कनिष्ठ आशुलिपिक
58.	**श्री एन. रामकृष्णा** प्रवर श्रेणी लिपिक
59.	**श्री एम सुधीर कुमार यादव** **प्रवर श्रेणी लिपिक**
60.	**श्री के. कृष्णमूर्ति** कारचालक (ग्रेड-२)
61.	**श्री बी. मल्लेश** ड्राइवर
62.	**श्री एस सत्यनारायण** ड्राइवर
63.	**श्री डी. यादय्या** स्टाफ कार ड्राइवर
64.	**मो. रहीम** स्टाफ कार ड्राइवर
65.	**श्री जी. एस. पद्मराव** बाईंडर
66.	**श्री एन. रघुपती** प्लम्बर

67.	**श्री सी.एन. रमेश यादव** रसोइया
68.	**श्री जी. नरसिम्हुलु** बहुकार्य कर्मचारी
69.	**श्री बी. यादगिरी** बहुकार्य कर्मचारी
70.	**श्री सी. नारायणा** बहुकार्य कर्मचारी
71.	**श्री जी. राजाबाबु** बहुकार्य कर्मचारी
72.	**श्री एन. जी. कोटय्या** बहुकार्य कर्मचारी
73.	**श्री बी. एल्लामय्या** बहुकार्य कर्मचारी
74.	**श्रीमति जी. विजया** बहुकार्य कर्मचारी
75.	**श्री एन. शिवलिंगम** बहुकार्य कर्मचारी
76.	**श्री बी. सत्तय्या** बहुकार्य कर्मचारी
77.	**श्री ए. हनुमंतु** बहुकार्य कर्मचारी
78.	**श्री टी. देवराज** बहुकार्य कर्मचारी

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-2020

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना, भारत
www.manage.gov.in